



Tamannaah Bhatia Requests...

नौकरशाही



डॉ. अजय मिश्रा

वनांचल के नौकरशाही वाले मोहल्ले में जबरदस्त हलचल मची है। बदलाव की तेज बयार ने सब कुछ उलट-पुलट दिया है। करीब दो दर्जन से अधिक हुक्मरान इधर से उधर हो गए हैं। अब इन बदलावों के पीछे के किस्से-कहानियों का दौर चल रहा है। कुछ लोग खुश हैं, कई चेहरों पर मायूसी है। इन सबके बीच असल खेल लोहे वाले नगर में हुआ। आखिर क्या कुछ चल रहा अंदरखाने, जानें द फोटोन न्यूज के एक्जीक्यूटिव एडिटर की कलम से।

पूजा घर से रामचरितमानस की पंक्तियां सुनाई दे रही थीं। नजदीक जाने पर पता चला कि गुरु पाठ कर रहे हैं। पहली चौपाई आई- 'बर दायक प्रनतारति भंजन। कृपासिंधु सेवक मन रंजन॥ इच्छित फल बिनु सिव अवराधे। लहिअ न कोटि जोग जप साधे'। फिर व्याख्या आई- 'गोस्वामी जी लिखते हैं- शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता।' रात को निकले शासनादेश पर सुबह-सुबह विमर्श की अभिलाषा लिए गुरु से मिलने पहुंचा था। कुछ झोलटन टाइप नौकरशाह पहले से जमे थे। लिहाजा मौन धारण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घंटे भर इंतजार के बाद पाठ समाप्त हुआ। नजर पड़ते ही गुरु ने

मन रंजन भंजन



फोटो प्रतीकात्मक रूप से एआई जनरेटेड है।

टोका- अरे यहाँ क्यों खड़े हो, आओ- आओ, यहाँ बैठो, सब अपने लोग हैं। उम्मीद थी, तुम्हारे दर्शन होंगे, लेकिन इतनी सुबह? सब सकुशल? गुरु ने सवाल किया, लिहाजा उत्तर देना था। सो, मुस्कुराते हुए कहा- हां गुरु, बस

चला आया। सोचा बता दूँ, आपकी एक भविष्यवाणी गलत हो गई। गुरु चौंक गए। बोले, मेरी गणना गलत! ऐसा कैसे? बताओ, क्या हुआ? जवाब दिया- लोहे की नगरी में सिटी ब्वॉय वाला शिफूफ! वाक्य पूरा होते ही गुरु हंस पड़े, बोले अरे यार कहां बात पकड़ कर बैठे हो? पांच अक्षर वाले नाम में दो पर टिके हो। तीन पर फोकस करो। सारी कृपा वहीं फंसी है। गुरु की यह बात सिर के ऊपर से निकल गई। अब इतना साफ हो गया कि ज्ञान का पिटाया खुलने वाला है। गुरु पूरे री में आ चुके थे। सो, मुख्य विषय पर लौटते हुए बोले, नौकरशाही के बाजार में 'रंजन' का बड़ा क्रेज है। बिल्कुल वैसा, जैसे कभी वनस्पति घों का मतलब डालडा। खैर कहानी सुनो। कथानक यह है कि सूची वाले रंजन करीब दस माह पहले धनुष भंजन करने वाले थे। ऐन वक्त पर सूर्य पुत्र का पंच फंस गया। इच्छा पूरी नहीं होने पर राजीव नवन लोचन से भर गए।

साधक ने फिर पूरे मनोयोग से घोर तपस्या की। आखिरकार शिव को वरदान के लिए मना लिया। तब समय पर साधना का प्रतिफल मिला। बहरहाल, जहां तक बात पूर्वानुमान की है, सारा भ्रम रंजन के कारण हुआ। एक हेवीवेट मोहतरमा ने अधूरी सूचना में एक छवि गढ़ दी। लिहाजा रंजन का लाभ लेकर शिफूफ पर जन-मन को यकीन होने लगा। इंतजार बस आदेश का था। शाम होते-होते सबकी घड़कनें तेज थीं। रात आते ही बात बदल गई। पात्र बदल गए। किरदार बदल गए। तुम्हारी बिरादरी के सूरमाओं ने तो और गजब कर डाला। पहले से यातायात के मोर्चे पर तैनात हमनाम हाकिम की तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड कर दी। सुबह से फोन पर सफाई देते घूम रहे हैं। गुरु की बातें समझ में आ चुकी थीं। प्रसंग ने प्रमाण का दामन थामकर भ्रम के अधिभारों को दूर कर दिया था। लिहाजा गुरु के हाथ जोड़े और विदा ली।

SARAFI

सोना	: 14,430
चांदी	: 280.00

(नोट : सोना 22 केरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

केंद्र सरकार ने 2 प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता

NEW DELHI : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत किया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले से सरकार का सालाना 6,791 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान किया गया।

पुणे में एयरफोर्स के विमान की हार्ड लैंडिंग

PUNE : पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हुई। रात 10-30 बजे हुई इस घटना के बाद रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। जिसके कारण एयरपोर्ट पर पलाइंट ऑपरेशन करीब 11 घंटे तक प्रभावित रहा। पुणे एयरपोर्ट के डायरेक्टर संतोष धोके ने बताया कि भारतीय वायु सेना के विमान को सुबह करीब 5.45 बजे रनवे से हटा दिया गया था। पलाइंट ऑपरेशन सुबह 7.30 बजे के बाद नॉर्मल हो सकी।

सीबीआई ने हार्डकोर्ट को दी जानकारी

झारखंड में एमपी-एमएलए से जुड़े 10 मामले हैं लंबित

PHOTON NEWS RANCHI : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड हार्डकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर बताया कि हाल ही में एमपी-एमएलए का एक मामला निपटारा गया है। वर्तमान में सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) से जुड़े केवल 10 मामले लंबित हैं। हार्डकोर्ट में एमपी-एमएलए के लंबित मामलों के जल्द निष्पादन को लेकर कोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई हार्डकोर्ट में

सभी आपराधिक केस को जल्द निष्पादित करने का आदेश है। मामले की सुनवाई हार्डकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में हुई। खंडपीठ ने सीबीआई से मौखिक रूप से कहा कि राज्य में एमपी-एमएलए के लंबित आपराधिक मामलों को जल्द निष्पादित करें। ट्रायल में देरी होने से गवाहों पर भी असर पड़ता है, उनकी गवाही प्रभावित होती है।

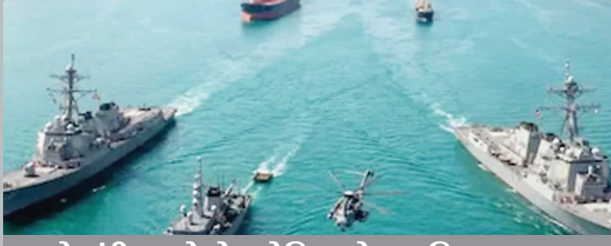
ईरान ने 24 घंटे के अंदर फिर से बंद कर दिया होर्मुज स्ट्रेट ईरानी सेना ने ब्रिटेन व भारत के जहाज पर की गोलीबारी

NEW DELHI @ PTI :

शनिवार को ईरान ने 24 घंटे के अंदर फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। इसे शुक्रवार को ही खोला गया था, लेकिन अब इस समुद्री रास्ते पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ईरान की सख्ती के बाद होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे दो जहाजों पर ईरान के गनबोट्स ने गोलीबारी की। इसमें भारत का भी एक जहाज शामिल था। ईरान के रिवालयुशनरी गार्ड की गोलीबारी की खबरों के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में दो जहाजों को अपना मार्ग बदलना पड़ा। टैंकरटैकसंडॉट कॉम ने बताया कि इन जहाजों में भारतीय ध्वज वाला एक सुपर टैंकर भी शामिल है, जो इराक से 20 लाख बैरल तेल ले जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को भारत में तैनात ईरान के राजदूत को तलब किया और इस

विदेश मंत्रालय ने घटना पर दर्ज कराया विरोध, ईरान के राजदूत तलब

- भारतीय ध्वज वाला सुपर टैंकर इराक से 20 लाख बैरल ले जा रहा था तेल
- अमेरिका पर लगाया सीजफायर डील तोड़ने का आरोप
- जब तक नहीं हटेगी नाकेबंदी, होर्मुज से जहाजों के गुजरने की अनुमति नहीं
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले- हर हाल में लेंगे ईरान का यूरेनियम



नाकेबंदी हटाने से अमेरिका ने कर दिया इनकार

ईरान ने साफ वेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक वह होर्मुज से जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर अमेरिका ने होर्मुज से नाकेबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब तक

दावा : अमेरिका-इजरायल व ब्रिटेन से जुड़े नेटवर्क ध्वस्त

ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका, इजरायल और ब्रिटेन से जुड़े कई कथित नेटवर्क का भंडाफोड़ कर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। यह जानकारी ईरान की इस्लामिक रिवालयुशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के खुफिया विंग के हवाले से सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये नेटवर्क जासूसी गतिविधियों में शामिल थे और देश के भीतर अपने संपर्क बढ़ाकर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आईआरजीसी के अनुसार, ये कथित सेल्स इंस्ट्रूमेंट अजरबैजान, कैमरून और माजदरान प्रांतों में सक्रिय थे, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्क्रिय कर दिया।

उसने भरोसे में आकर कुछ तेल और माल ले जाने वाले जहाजों को गुजरने दिया था। लेकिन, अमेरिका ने अपने वादे नहीं निभाए और नाकेबंदी के बहाने जहाजों के साथ सख्ती की। ईरान ने कहा कि यह सीजफायर

डाउनलोड करने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर आया एरर अचानक जारी हुआ 10वीं का रिजल्ट, फिर गायब

PHOTON NEWS RANCHI :

शनिवार को सुबह झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के 10वीं बोर्ड रिजल्ट को लेकर अचानक अफवाह फैल गई। कई विद्यार्थियों को जानकारी मिली कि जैक की वेबसाइट पर मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वेबसाइट पर जाकर रोल कोड और रोल नंबर दर्ज किया, जिसके बाद कुछ देर के लिए बच्चों को रिजल्ट दिखाते लगा। लोहरदगा जिले के कुडू और कैरो प्रखंड के कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपना रिजल्ट ऑनलाइन डाउनलोड भी कर लिया।

रांची और लोहरदगा में कई बच्चों ने डाउनलोड किया अपना रिजल्ट

- कुछ स्कूलों ने तैयार कर ली अपने टॉपर्स की सूची
- जैक ने बताया फर्जी, कहा- ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द जारी होगा रिजल्ट

स्क्रीनशॉट वायरल
कई छात्रों की माइक्रोसॉफ्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसमें स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम और विषयवार अंक अंकित थे। स्क्रीनशॉट में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 भी स्पष्ट रूप से दर्ज था। देर रात तक लिंक सक्रिय होने और सुबह तक रिजल्ट दिखने के बाद हटाए जाने से गड़बड़ी या किसी अन्य कारण की आशंका जताई जा रही है।

अफवाहों से बचने की अपील

इस मामले में जैक के सचिव जयंत मिश्रा ने काउंसिल की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि हम लोगों ने अभी रिजल्ट जारी नहीं किया है। तब समय पर इसे जारी किया जाएगा। काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर और अखबारों में इसकी सूचना जारी की जाएगी। जो रिजल्ट जारी होने की सूचना मिली है, वह सही नहीं है। इस तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से अफवाहों से बचने की अपील की है।

वहीं, रांची के सिल्ली इलाके में भी बच्चों ने अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लिया। कुछ स्कूलों ने अपने टॉपर्स की सूची तैयार कर ली। हालांकि कुछ समय बाद वेबसाइट पर एरर आने लगा और रिजल्ट दिखना बंद हो गया।

वैंड सक्सेस लंबे प्रयासों के बाद अंजाम तक पहुंचा अनुसंधान अभियान 'मिशन मित्र'

अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों को मात देने की निकली राह इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने मिशन को सफल बनाने के लिए दिन-रात किया काम

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK :

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार, ब्रह्मांड का यह विस्तार को पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद रहता है, अंतरिक्ष कहलाता है। इसका बाहरी स्थान पूरी तरह से खाली नहीं है। यह एक कठोर निर्वात यानी शून्य है, जिसमें कणों का घनत्व कम होता है। मुख्य रूप से यहां हाइड्रोजन और हीलियम की तरल अवस्था के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण और चुंबकीय क्षेत्र घुल के साथ उपलब्ध होता है। ऐसे क्षेत्र में मानव यात्रा के दौरान कई प्रकार की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की है। वंदे इन पहले इसरो की ओर से अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों को मात देने की कारगर राह निकाल गई है। देश के मानव अंतरिक्ष मिशन को निरूपित स्थिति में आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इसरो ने लड़ाकू में अपने उच्च-ऊंचाई अनुसंधान अभियान 'मिशन मित्र' को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने दिन-रात काम किया।

4000 मीटर की ऊंचाई पर लगातार पांच दिनों तक प्रयोग का किया गया संचालन

उच्च दबाव व अपरिचित परिस्थितियों में की गई मानव व्यवहार की एनालिटिकल स्टडी

मिशन से प्राप्त वैज्ञानिक डेटा भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम और भविष्य के दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह मिशन इसरो और भारतीय वायु सेना के अंतर्गत इस्टैट्यूट ऑफ एयरोस्पेस में मिशन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया, जबकि बैंगलुरु स्थित स्टार्टअप प्रोटोप्लानेट ने इसकी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की। पांच दिनों के दौरान

प्रोटोप्लानेट की लॉजिस्टिक सहायता

प्रतिभागियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से प्रेरित एक सख्त टाइम टेबल के तहत रखा गया, जिसमें हर गतिविधि सुबह उठने से लेकर मेडिकल डेटा लॉगिंग तक सटीक समय पर की गई। मिशन के बारे में जानकारी देते हुए इसरो के ह्यूमन स्पेस प्लाइट सेंटर के थुपा डायरेक्टर एके सिन्हा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य उच्च दबाव और अपरिचित परिस्थितियों में मानव व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना था।



कम ऑक्सीजन की समस्या का निराकरण

यह पांच दिवसीय मिशन लेह के निकट लिफ्टर गांव के आसपास लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर संचालित किया गया। वैज्ञानिकों की ओर से यह जानकारी दी गई है कि मिशन मित्र

का दूसरा उद्देश्य अंतरिक्ष मिशनों के दौरान आने वाली चुनौतियों जैसे हाइपोक्सिया, अल्टीटिक डेड, एकांत और सीमित संसाधन का व्यासंग्य वास्तविक अनुकरण और निराकरण करना था।

अगले तीन दिनों में 2-3 डिग्री बढ़ सकता है मैक्सिमम टेंपरेचर

तीखी तपिश ने बढ़ाई परेशानी, आठ जिलों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी

PHOTON NEWS RANCHI :

अब झारखंड में गर्मी ने भीषण रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से तापमान में वृद्धि के कारण तीखी तपिश की स्थिति है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाके लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने 20 और 21 अप्रैल को राज्य के 8 जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और खूंटी शामिल हैं।

डाल्टनगंज का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक



रांची में 41 डिग्री जाणा पारा

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची में 20 व 21 अप्रैल को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और पश्चिमी दिशा से एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, हिमालयी क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल होते हुए सक्रिय हो रहा है। इससे प्रभाव से आने वाले दिनों में झारखंड समेत आसपास के राज्यों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान गुमला में 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है।



न्यायिक सुधारों को रेखांकित करती लाल बंगला



गुमनाम है कोई...

फिल्म की शुरुआत एक व्यक्ति मंगू (शेख मुख्तार) के तीन साल बाद जेल से छूटने से होती है। कहानी आगे बढ़ने पर हम जानते हैं कि मंगू के जेल जाने के बाद उसकी बीवी पर चुकी है और उसकी बच्ची अनार्यों की तरह पल रही है। मंगू अपनी बच्ची को लेकर सीधे उसे गिरफ्तार करवाने वाले सेठ (राजन हक्सर) के पास पहुंचता है, जहां पता चलता है कि अपने गुनाह छिपाने के लिए सेठ जी ने मंगू को चोरी के झूठे आरोप में फंसा कर जेल भिजवाया था। सेठ जब उसे उसकी पुरानी नौकरी वापस देने से इनकार कर देता है तो मंगू उसे गिरफ्तार करने वाले इन्स्पेक्टर कपूर (पृथ्वी राज कपूर) के पास पहुंचता है और उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि उसे गलत आरोपित किया गया है। पर इन्स्पेक्टर कपूर जो अब एस पी बन चुके हैं, उनसे मंगू को कोई हमदर्दी नहीं मिलती है और निराश मंगू वहाँ से निकल कर जुम और अपराध की दुनिया में चला जाता है। सालों बाद मंगू अब दुनिया की नजरों में एक इज्जतदार सेठ दीनदयाल बन चुका है। पर मूलतः वो एक संफेदपोश अपराधी है। एसपी साहब के दोनों बेटे अब बड़े हो चुके हैं, बड़ा बेटा शंकर (जुगल किशोर) सीआईडी ऑफिसर बन चुका है और छोटा बेटा राजा (सुजीत कुमार) क्या करता है यह पता नहीं पर पहाड़ों में गाने गाता दिखाई दे रहा है। इधर मंगू उर्फ सेठ दीनदयाल की बेटी मालती (जयन्ती) भी बड़ी हो गई है और उसकी दोस्ती राजा से हो चुकी है। सीआईडी बने शंकर को शहर के जिस गैंग की तलाश है उससे जुड़ी एक फाइल चुराने के लिए मंगू मदद लेता है बेला (श्यामा) की। पर वो असफल रहती है। इसी बीच मालती और राजा की दोस्ती और प्यार की खबर सेठ दीनदयाल को मिलती है और वो अपने गैंग की बेला को ये जिम्मा देता है कि बेला राजा से इस तरह मेल जोल बढ़ा ले कि राजा, मालती को भूल जाए। बेला को यहाँ भी असफलता मिलती है। इधर जब सेठ दीनदयाल

को अवसर मिलता है तो वो दुबारा से शंकर की फाइल चुराने के लिए अपने आदमी भेजता है। ये आदमी भी असफल रहते हैं और शंकर इनका पीछा करता घाटी की तरफ जाने लगता है तभी शंकर को पहाड़ी पर खंडहर में एक भूतनी दिखाई देती है। इस भूतनी के चक्कर में फाइल चोर शंकर के हाथ से निकाल जाता है। शंकर जब यह बात अगले दिन अपने एसपी पिता को बताता है तो उन्हें भूत-प्रेत की कहानी पर भरोसा नहीं होता और शंकर अपने सहायक शंभू (मोहन चोटी) के साथ फिर उन्हीं खंडहरों में जाता है, यहाँ खंडहर में भूतनी फिर दिखाई देती है और इस चक्कर में असमंजस में डूबे शंकर पर मौका देख कर सेठ दीनदयाल गोली चल देता है। गोली शंकर के बाजू में लगती है और वो घायल हो जाता है। बच कर भागते दीनदयाल का पीछा करता शंकर बेहोश हो जाता है और मालती को मिल जाता है। मालती उसे घर ले कर आती है और उसका इलाज करवाती है। घर पहुँच कर दीनदयाल जब शंकर के लिए मालती को परेशान देखता है तो वो मौके का फायदा उठाते हुए एसपी साहब से राब्ता बनाने की कोशिश करता है। एसपी साहब भी अपने बच्चे की जान बचाने वालों के प्रति नरमी दिखाते हैं पर सेठ दीनदयाल के रूप में मंगू को पहचान नहीं पाते। यहाँ से फिल्म की गति तेज हो जाती है और घात, प्रतिघात और चालों का एक दिलचस्प घटना क्रम देखने को मिलता है जहाँ सीआईडी इन्स्पेक्टर भाई अपने सगे भाई को फांसी के फंदे तक ले जाता है। अंत में सभी को उनके किए के हिसाब से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, थोखा देने वालों को सजा मिलती है, मुगालतों में जीने वालों को समझ और नायक को मिलती है नायिका।

हिन्दी सिनेमा के लिए साल 1966 काफी यादगार साल रहा, इस साल सिनेमा घरों में मेरा साया, तीसरी मंजिल और ये रात फिर ना आएगी जैसी रहस्य रोमांच श्रेणी की फिल्में आईं और सफल रहीं, वहीं दूसरी ओर दर्शकों ने ममता, अनुपमा, देवर, सूरज और दो बदन जैसी रोमांटिक और सामाजिक फिल्मों को भी दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। उस बरस ने हिन्दी सिनेमा को कई कालजयी गीत दिए। या दिल के सुनो दुनिया वालों, कुछ दिल ने कहा (अनुपमा), छुपा लो यू दिल में प्यार, रहें ना रहे हम (ममता), ले गईं दिल गुड़िया जापान की (लव इन टोवो), बहारों फूल बरसाओ (सूरज) के अलावा तीसरी मंजिल, मेरा साया जैसी फिल्मों के गीत आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं।

शेख मुख्तार, पृथ्वी राज कपूर जैसे समर्थ अभिनेता, बेहतरीन गीत और शानदार लोकेशन्स पर शूट हुई यह फिल्म अपने समय में सफल फिल्म रही थी। फिल्म का एक गीत 'चाँद को क्या मालूम' आज भी मुकेश के सबसे यादगार गीतों की हर लिस्ट में मौजूद पाया जाता है। फिल्म का निर्माण और निर्देशन, फिल्म में शंकर की भूमिका निभाने वाले जुगल किशोर ने किया था। कहानी हरि जुत्सी, पटकथा राजेश नंदा और संवाद बृज कल्याल के थे। फिल्म में कुल गीत थे, गुलशन बावरा, विनोद शर्मा और इंदीवर के लिखे इन गीतों को सुरों से सजाया था उषा खन्ना ने और इन गीतों को मुकेश, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और सुमन कल्याणपुर के साथ खुद उषा खन्ना ने अपनी आवाज दी थी। फिल्म में कुछ कमाल के फाइट सीक्वेंस थे जिन्हें बुरहानुद्दीन के निर्देशन में रचा गया था। लाल बंगला का बड़ा हिस्सा हिमांचल प्रदेश के कांगड़ा, धर्मशाला और पालनपुर टी एस्टेट में शूट हुआ था और फिल्म के गीतों और चेज सीक्वेंस में वो खूबसूरत वादियाँ हंम बहुत मनमोहक स्वरूप में दिखाई देती हैं।

लघुकथा

एक अनकहा रिश्ता

हम अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि वे बहुत संपन्न या प्रसिद्ध हों, कई बार एक साधारण और अभावों में जीने वाला व्यक्ति भी हमें गहराई से छू जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति और उससे जुड़ी एक घटना का जिक्र कर रही हूँ, जिसने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ दी।



गीता दुबे

पिछले वर्ष की बात है। घर में चूना-पोताई का काम खत्म होने के बाद खिड़की-दरवाजे पर पॉलिश के काम के लिए हमें मजदूर की तलाश थी, चूँकि दीपावली का समय था, इसलिए पॉलिश करने वाला कोई मिल नहीं रहा था, काफी खोजबीन के बाद एक युवक मिला, नाम था असलम, उम्र यही कोई 35-40 के बीच। वह घर आया, चारों ओर देखा और बोला- 'इस काम में पूरा एक महीना लग जाएगा'।

हमने आश्चर्य से कहा- 'एक महीना?' वह शांत स्वर में बोला- 'मैं अकेला ही काम करूँगा। अगर आपको ठीक लगे तो बोलिए, नहीं तो आप किसी और को रख लीजिए'। उसकी स्पष्टता में एक सच्चाई थी, सो हमने हाँ कर दी।

अगले ही दिन से उसका काम शुरू हो गया। वह रोज समय से पहले आ जाता और पूरे मन से काम में लग जाता। खिड़कियाँ और दरवाजों को वह इस तरह पॉलिश करता, मानो उन्हें सजा नहीं रहा, बल्कि सवार रहा हो। काम के प्रति उसकी लगन अद्भुत थी, न कोई आलस्य, न कोई दिखावा। कोई देखे या न देखे, वह अपने काम में डूबा रहता। दोपहर के खाने के लिए भी वह मुश्किल से कुछ मिन्टों के लिए ही जाता और तुरंत लौटकर फिर काम में लग जाता। उसकी एकाग्रता ऐसी थी कि यदि कोई उससे बात भी करता, तो वह बस हल्का सा उत्तर देकर फिर अपने काम में खो जाता, यहाँ तक कि रिवार को भी वह छुट्टी नहीं लेता।

एक दिन अचानक वह नहीं आया। हमने फोन लगाया, पर उसका मोबाइल बंद था। चिंता हुई, देर रात करीब दस बजे उसने फोन ऑन किया। हमने तुरंत पूछा- 'आज क्यों नहीं आए?' उसने धीमे स्वर में कहा- 'मेरे बाबूजी नहीं रहे'।

हम घुप रह गए। स्वाभाविक था कि वह कुछ दिन नहीं आया, पर उसने खुद ही कहा- 'मैं कल से काम पर आऊँगा'।

बातों-बातों में पता चला कि उसके हबाबूजी शहर के एक समृद्ध इलाके में रहते थे। यह जानकर आश्चर्य हुआ, हमने पूछा- 'तुम वहाँ क्यों नहीं रहते?' फिर धीरे-धीरे उसकी कहानी खुली- जब वह लगभग चौदह वर्ष का था, तब गरीबी ने उसे काम की तलाश में घर से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। उसी

दौरान उसकी मुलाकात बलभद्र सिंह से हुई, जिन्होंने उसे अपने घर में नौकर के रूप में काम दे दिया। वर्षों की सेवा और स्नेह ने उसे उस परिवार के इतना करीब ला दिया कि जब उस घर का असली, इकलौता बेटा एक दुर्घटना में चल बसा और बेटे के जाने के शोक में बाद में बेटे की माँ भी चल बसी, तो उस अकेले पड़े पिता (बलभद्र सिंह) ने असलम से कहा- 'आज से तुम ही मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाबूजी'। यह कोई औपचारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि दिल से निकला हुआ संबंध था। समाज और रिश्तेदार भी उसे उसी रूप में स्वीकार करने लगे।

आगे चलकर असलम, शादी के बाद बाबूजी की बात मानकर पॉलिश का काम सीख लिया और परिवार लेकर अलग रहने लगा। लेकिन वह अपने बाबूजी से हमेशा जुड़ा रहा, उनका हालचाल लेता रहता, कभी-कभार मिलने भी बला आता, उसने अपनेपन की वह डोर कभी टूटने नहीं दी।

उस रात अचानक हृदयाघात से 'बाबूजी' के निधन की खबर मिलते ही वह दौड़ा चला गया। वैसे तो बाबूजी का परिवार बहुत बड़ा था, भाई-भतीजों से भरा हुआ, लेकिन जब उनके अंतिम समय की घड़ी आई, जब उनके क्रिया-कर्म की जिम्मेदारी निभाने का वक्त आया तब कोई सामने नहीं आया। एक-एक कर सब पीछे हटते चले गए। आखिर हमसे अपने बाबूजी का अंतिम संस्कार किया, उन्हें मुखाग्नि देकर बेटे होने का कर्तव्य निभाया। उसने धर्म का भेद नहीं देखा, उस समय वह केवल एक बेटा था, अपने 'बाबूजी' को विदा करता हुआ।

उसकी बातें सुनकर मैं लंबे समय तक मौन रही। मन में बस एक ही विचार बार-बार उठता रहा, 'इंसान वास्तव में प्रेम का भूखा होता है, न वहाँ धर्म का भेद था, न अमीरी-गरीबी की दीवार। वहाँ केवल सच्चा स्नेह था, जो खून के रिश्तों से भी अधिक गहरा और पवित्र था।

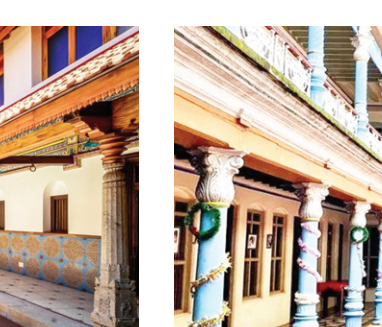
दक्षिण भारत की परंपराओं का 'स्वाद'

दिल्ली की उस सुबह मैं एक अलग ही उत्साह था। सर्द हवा के बीच जब मैंने घर का दरवाजा बंद किया, तो मन में एक नई यात्रा की हल्की-सी धड़कन महसूस हो रही थी। रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ समय दूर जाकर भारत की किसी ऐसी जगह को देखने की इच्छा थी, जहाँ इतिहास और परंपरा आज भी जीवित हों। कई दिनों से मैं दक्षिण भारत के एक खास क्षेत्र के बारे में पढ़ रहा था- चेत्तीनाड। कहा जाता है कि यह स्थान अपनी भव्य हवेलियों, अनोखी वास्तुकला और प्रसिद्ध व्यंजनों के कारण देश-विदेश के यात्रियों को आकर्षित करता है। यही सोचकर मैंने इस यात्रा की योजना बनाई और दिल्ली से चेत्तीनाड की ओर निकल पड़ा।



दरवाजे और मजबूत दीवारें यह बता रही थीं कि कभी यहाँ समृद्धि और वैभव का अद्भुत संगम रहा होगा।

मैंने सबसे पहले एक पारंपरिक हवेली को देखने का निश्चय किया। जैसे ही मैं उस हवेली के मुख्यद्वार के सामने पहुँचा, उसकी नक्काशीदार बनावट ने मुझे कुछ क्षणों के लिए वहीं रोक दिया। दरवाजे को पार करते ही अंदर का दृश्य और भी प्रभावशाली दिखाई दिया। विशाल 'खंबे', जिन पर बारीक कारीगरी की गई थी, उस जगह की शान को और बढ़ा रहे थे। दीवारों पर लगे बड़े शीशे और चमकदार संगमरमर का फर्श इस बात का प्रमाण दे रहे थे कि उस समय के लोग कला और सौंदर्य को कितना महत्व देते थे। हवेली के भीतर कदम रखते ही एक विशाल आँगन दिखाई दिया, जहाँ घुप की किरणें सीधे जमीन पर गिर रही थीं। उस खुले स्थान में खड़े होकर मुझे एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। चारों ओर फैली खामोशी और व्यवस्थित संरचना यह महसूस करा रही थी कि यह जगह केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि एक परंपरा का प्रतीक है।



रंजन शेखर्द नई दिल्ली

इसी दौरान मेरी नजर फर्श पर पड़ी और मैं उसकी सुंदरता को देखकर चकित रह गया। रंग-बिरंगी अर्थगुडी टाइल्स का आकर्षक पैटर्न पूरे वातावरण को जीवंत बना रहा था। इन टाइल्स की चमक और रंगों का संतुलन इतना सुंदर था कि उन्हें देखकर मन में कारीगरों की मेहनत के प्रति सम्मान पैदा हो गया। जब मैंने उन टाइल्स पर धीरे-धीरे कदम रखा तो उनकी ठंडक ने मुझे तुरंत सूकून का एहसास कराया।

उस क्षण मुझे यह महसूस हुआ कि मेरी यह यात्रा केवल एक नई जगह देखने तक सीमित नहीं है। यह अनुभव मुझे भारत की कला, परंपरा और जीवनशैली के उस पहलू से परिचित करा रहा था, जिसे अक्सर हम अपनी व्यस्त जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। हवेली के उस



नया देखने को मिल रहा था। कहीं मसालों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, तो कहीं पारंपरिक वस्तुएँ सजी हुई थीं। दुकानदार बड़े उत्साह से अपने सामान के बारे में बताते और ग्राहकों से मुस्कुराकर बातचीत करते नजर आ रहे थे।

मैंने भी अपनी यात्रा की याद के रूप में कुछ चीजें खरीदने का निर्णय लिया। मैंने स्थानीय मसालों का एक छोटा पैकेट लिया, थांकि घर लौटने के बाद भी इस जगह की खुशबू मेरे साथ बनी रहे। इसके अलावा एक छोटा-सा पारंपरिक बर्तन भी खरीदा, जो मुझे हमेशा इस यात्रा की याद दिलाता रहेगा।

शाम होने लगी थी और आसमान का रंग धीरे-धीरे बदल रहा था। सूरज की किरणें पूरे वातावरण को सुनहरी आभा से भर रही थीं। उस शांत दृश्य को देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक स्थान देखने की नहीं थी, बल्कि अपने देश की संस्कृति और परंपराओं को समझने की यात्रा थी।

अगले दिन जब वापसी का समय आया तो मन में एक हल्की-सी उदासी भी थी और संतोष भी। उदासी इसलिए कि एक सुंदर अनुभव पीछे छूट रहा था और संतोष इसलिए कि इस यात्रा ने मुझे नई यादें और नई समझ दी थी। स्टेशन की ओर जाते हुए मैं बार-बार उस शांत वातावरण को देख रहा था, जिसने इतने कम समय में मेरे दिल में एक खास जगह बना ली थी।

दिल्ली लौटते समय ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि यह यात्रा केवल एक साधारण भ्रमण नहीं थी। यह एक ऐसा अनुभव था, जिसने मुझे भारतीय परंपराओं, कला और स्वाद की गहराई से परिचित कराया। अब जब भी मैं उस यात्रा को याद करता हूँ तो चेत्तीनाड (मिलनाड) की सड़कों, वहाँ के लोगों का अपनापन और उस जगह की सुगंध मेरे मन में फिर से जीवंत हो उठती है।

घुमवकड़ की पाती

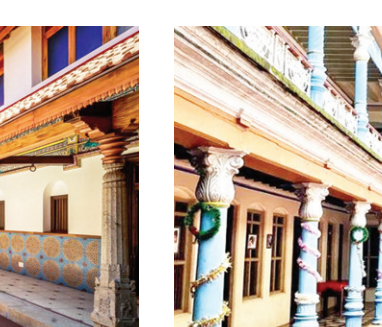
दक्षिण भारत की परंपराओं का 'स्वाद'



दरवाजे और मजबूत दीवारें यह बता रही थीं कि कभी यहाँ समृद्धि और वैभव का अद्भुत संगम रहा होगा।

मैंने सबसे पहले एक पारंपरिक हवेली को देखने का निश्चय किया। जैसे ही मैं उस हवेली के मुख्यद्वार के सामने पहुँचा, उसकी नक्काशीदार बनावट ने मुझे कुछ क्षणों के लिए वहीं रोक दिया। दरवाजे को पार करते ही अंदर का दृश्य और भी प्रभावशाली दिखाई दिया। विशाल 'खंबे', जिन पर बारीक कारीगरी की गई थी, उस जगह की शान को और बढ़ा रहे थे। दीवारों पर लगे बड़े शीशे और चमकदार संगमरमर का फर्श इस बात का प्रमाण दे रहे थे कि उस समय के लोग कला और सौंदर्य को कितना महत्व देते थे। हवेली के भीतर कदम रखते ही एक विशाल आँगन दिखाई दिया, जहाँ घुप की किरणें सीधे जमीन पर गिर रही थीं। उस खुले स्थान में खड़े होकर मुझे एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। चारों ओर फैली खामोशी और व्यवस्थित संरचना यह महसूस करा रही थी कि यह जगह केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि एक परंपरा का प्रतीक है।

इसी दौरान मेरी नजर फर्श पर पड़ी और मैं उसकी सुंदरता को देखकर चकित रह गया। रंग-बिरंगी अर्थगुडी टाइल्स का आकर्षक पैटर्न पूरे वातावरण को जीवंत बना रहा था। इन टाइल्स की चमक और रंगों का संतुलन इतना सुंदर था कि उन्हें देखकर मन में कारीगरों की मेहनत के प्रति सम्मान पैदा हो गया। जब मैंने उन टाइल्स पर धीरे-धीरे कदम रखा तो उनकी ठंडक ने मुझे तुरंत सूकून का एहसास कराया।



रंजन शेखर्द नई दिल्ली

इस यात्रा को याद रखते हुए मुझे एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। चारों ओर फैली खामोशी और व्यवस्थित संरचना यह महसूस करा रही थी कि यह जगह केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि एक परंपरा का प्रतीक है।

उस क्षण मुझे यह महसूस हुआ कि मेरी यह यात्रा केवल एक नई जगह देखने तक सीमित नहीं है। यह अनुभव मुझे भारत की कला, परंपरा और जीवनशैली के उस पहलू से परिचित करा रहा था, जिसे अक्सर हम अपनी व्यस्त जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। हवेली के उस

नया देखने को मिल रहा था। कहीं मसालों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, तो कहीं पारंपरिक वस्तुएँ सजी हुई थीं। दुकानदार बड़े उत्साह से अपने सामान के बारे में बताते और ग्राहकों से मुस्कुराकर बातचीत करते नजर आ रहे थे।



मैंने भी अपनी यात्रा की याद के रूप में कुछ चीजें खरीदने का निर्णय लिया। मैंने स्थानीय मसालों का एक छोटा पैकेट लिया, थांकि घर लौटने के बाद भी इस जगह की खुशबू मेरे साथ बनी रहे। इसके अलावा एक छोटा-सा पारंपरिक बर्तन भी खरीदा, जो मुझे हमेशा इस यात्रा की याद दिलाता रहेगा।

शाम होने लगी थी और आसमान का रंग धीरे-धीरे बदल रहा था। सूरज की किरणें पूरे वातावरण को सुनहरी आभा से भर रही थीं। उस शांत दृश्य को देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक स्थान देखने की नहीं थी, बल्कि अपने देश की संस्कृति और परंपराओं को समझने की यात्रा थी।

अगले दिन जब वापसी का समय आया तो मन में एक हल्की-सी उदासी भी थी और संतोष भी। उदासी इसलिए कि एक सुंदर अनुभव पीछे छूट रहा था और संतोष इसलिए कि इस यात्रा ने मुझे नई यादें और नई समझ दी थी। स्टेशन की ओर जाते हुए मैं बार-बार उस शांत वातावरण को देख रहा था, जिसने इतने कम समय में मेरे दिल में एक खास जगह बना ली थी।

दिल्ली लौटते समय ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि यह यात्रा केवल एक साधारण भ्रमण नहीं थी। यह एक ऐसा अनुभव था, जिसने मुझे भारतीय परंपराओं, कला और स्वाद की गहराई से परिचित कराया। अब जब भी मैं उस यात्रा को याद करता हूँ तो चेत्तीनाड (मिलनाड) की सड़कों, वहाँ के लोगों का अपनापन और उस जगह की सुगंध मेरे मन में फिर से जीवंत हो उठती है।

BRIEF NEWS

रांची में एनएचआई की भर्ती परीक्षा 27 को

RANCHI : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने अकाउंटेंट पदों पर सीधी भर्ती के लिए 27 अप्रैल को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर होगी। इस संबंध में एनएचआई के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार को पत्र लिखकर परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासनिक और पुलिस सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। एनएचआई ने राज्य प्रशासन से अनुरोध किया है कि परीक्षा केंद्र पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं।

स्थानांतरित आईएस-आईपीएस अधिकारियों ने दिया योगदान

RANCHI : झारखंड सरकार द्वारा किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद अधिकारियों ने नए पदों पर कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। शुक्रवार देर रात जारी आदेश के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईपीएस) के 17 अधिकारियों में से अधिकतर ने शनिवार को अपने स्थानांतरित पदों पर योगदान दे दिया। इन सभी अधिकारियों को जिलों का उपायुक्त (डीसी) बनाया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के विशेष सचिव व अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय राजीव रंजन अपने स्थानांतरण के बाद पूर्वी सिंहभूम डीसी का कामकाज संभाला। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम आवास में औपचारिक मुलाकात भी की। वहीं भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के स्थानांतरित 46 अधिकारियों ने भी अपने-अपने नए पदों पर योगदान दे दिया है। इन अधिकारियों में कई जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शामिल हैं, जिन्होंने नई जिम्मेदारी संभालते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया है।

केंद्र सरकार ने बढ़ाया डीए-डीआर, सांसद ने किया स्वागत

RANCHI : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनधारियों के महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस फैसले का देशभर में व्यापक स्वागत हो रहा है। राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए राहत लेकर आया है। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ उनकी क्रय शक्ति को भी मजबूत करेगा।

चेतावनी : बढ़ रहा तापमान, लू और गर्म हवाओं से बचकर रहना जरूरी

PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के तहत जारी इस एडवाइजरी में लोगों को गर्म हवाओं और तेज धूप से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतने की अपील की गई है। जारी एडवाइजरी के अनुसार, लू और अत्यधिक गर्म हवाओं का स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इससे शरीर में पानी की कमी, उल्टी, तेज बुखार, कमजोरी, सिरदर्द और चक्कर आने जैसी समस्या हो सकती है।



गंभीर स्थिति में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर समस्याएं भी हो सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय बेजहज घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। विभाग ने गर्मी से बचाव के लिए नियमित रूप से प्यापित मात्रा में पानी पीने, नमक-चीनी का घोल, ओआरएस, नींबू पानी, आम का शरबत और लस्सी का सेवन करने की सलाह दी है। इसके साथ ही तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फलों और सब्जियों के सेवन पर जोर दिया गया है।

सावधानी बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई एडवाइजरी

- शरीर में पानी की कमी, उल्टी, तेज बुखार, कमजोरी, सिरदर्द और चक्कर आने जैसी हो सकती है समस्या
- गंभीर स्थिति में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होने की भी संभावना

इस प्रकार तैयार करें ओआरएस का घोल
ओआरएस घोल बनाने का तरीका भी बताया गया है। एक लीटर साफ पानी में ओआरएस का पूरा पैकेट घोलकर थोड़े-थोड़े अंतराल पर पीने की सलाह दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तैयार घोल का उपयोग 24 घंटे के भीतर कर लेना चाहिए। यह भी बताया गया है कि ओआरएस के पैकेट सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों और सहिया के पास नि:शुल्क उपलब्ध हैं। जहां से कोई भी इसे ले सकता है।

लू लगने की स्थिति में करें ये काम
स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसे तुरंत छांव में लिटाए, तग कपड़े ढीले करें, ठंडे गीले कपड़े से शरीर पोछे या ठंडे पानी से नहलाए। यदि एक घंटे तक स्थिति में सुधार नहीं होता है तो तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाएं। साथ ही लोगों को हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने, धूप का चश्मा, टोपी या गमछा इस्तेमाल करने की अपील की गई है। साथ ही बाहर निकलते समय शरीर को पूरी तरह ढकने की सलाह दी गई है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या शिकायत के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करने को कहा गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया राज्य को आयुष्मान भारत के लिए सम्मानित

झारखंड नंबर वन, रांची का सदर अस्पताल बना राष्ट्रीय रोल मॉडल

PHOTON NEWS RANCHI :

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड ने पूरे देश में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिबिर में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस उपलब्धि के लिए राज्य को सम्मानित किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह निरंतर मेहनत, प्रतिबद्धता और टीमवर्क का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा कर दिखाया गया है। आगे भी जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से सदर अस्पताल रांची की सराहना करते हुए कहा कि यह अस्पताल आज देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत

निरंतर मेहनत और टीमवर्क का परिणाम : डॉ. इरफान अंसारी



सरकारी अस्पतालों में 666 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू
झारखंड में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की बंपर वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने जेपीएससी को अधिवाचना पत्र भेज दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा मिल पाएगी। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए 666 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग को अधिवाचना पत्र भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि इस बहाली से सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी। मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि यह बहाली झारखंड राज्य के गैर-शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (भर्ती, प्रोन्टिस्ट एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015 एवं इसके संशोधित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। आरक्षण रोस्टर के साथ अधिवाचना जेपीएससी को भेज दी गई है, जिससे चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कीर्तिमान बनाएगा प्रदेश : अजय सिंह
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह सफलता राज्य की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, पारदर्शिता और टीमवर्क का परिणाम है। उन्होंने सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और संबंधित टीम को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि झारखंड आगे भी स्वास्थ्य सेवाओं में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस कार्यक्रम में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की टीम में छवि रंजन, सीमा सिंह, वैभव राय, डॉ. अखिलेश कुमार झा और अशीष रंजन ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान रांची सदर अस्पताल के उपकुशल कार्यों को देशभर के प्रतिनिधियों के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।

नंबर वन बनकर एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है। उन्होंने इसे पूरे झारखंड के स्वास्थ्य तंत्र की सामूहिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान राज्य के मजबूत

संकल्प और टोस कार्यों का परिणाम है। यह उपलब्धि न केवल झारखंड का गौरव बढ़ाने

वाली है, बल्कि स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सकों के मनोबल को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

रांची के नए ग्रामीण एसपी ने संभाला पदभार, कहा-

अपराध मुक्त योजना पर होगा काम

PHOTON NEWS RANCHI :

राजधानी रांची के नए ग्रामीण एसपी के तौर पर आईपीएस अधिकारी गौरव गोस्वामी ने शनिवार को अपना कार्यभार संभाला। इससे पूर्व गौरव गोस्वामी रिमार्क के पतरातू में एसडीपीओ के पद पर तैनात थे। शनिवार को सहायक पुलिस अधीक्षक के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद ग्रामीण एसपी ने बताया कि रांची के ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के अपराधिक वारदात हो रहे हैं, उसका विश्लेषण करने के बाद सभी तरह के हॉटस्पॉट को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिससे की ग्रामीण इलाके को हर तरह के अपराध से मुक्त किया जा सके। ग्रामीण लोगों से संपर्क कर पुलिस

किया जाएगा आंकड़ों का विश्लेषण : गौरव गोस्वामी

ग्रामीण एसपी ने बताया कि राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध का ग्राफ किस तरह का है, इसका संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। राजधानी की पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए ग्रामीण इलाके को सुरक्षित करना बेहद आवश्यक होता है। आईपीएस गौरव गोस्वामी ने बताया कि पूर्व ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के द्वारा बेहतरीन काम किया गया था, उन सभी कामों को वह आगे बढ़ाएंगे।

देवघर हुआ प्रवीण पुष्कर का तबादला

गौरतलब है कि शुक्रवार की देर रात झारखंड के पुलिस महकमे में फेर बदल करते हुए एक साथ 46 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। रांची के ग्रामीण एसपी रहे प्रवीण पुष्कर को देवघर का नया एसपी बनाया गया है। वहीं प्रवीण पुष्कर की जगह रांची के नए ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी को बनाया गया है।

पदाधिकारी उनकी समस्याएं सुनें की कोशिश करें। पुलिस के प्रति तथा थाना स्तर पर ही उसके निपटारे विश्वास बढ़ाना प्राथमिकता होगी।

प्रेमिका की मौत के बाद युवक ने फांसी लगाकर दी जान, मिला वीडियो

RANCHI :

कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित श्रद्धानंद रोड में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान संगम मांझी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से दुमका का रहने वाला था और रांची में एक व्यक्ति के यहां काम करता था। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार संगम मांझी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में थाने में युद्धी (अप्रकृतिक मृत्यु) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कुछ दिन पहले संगम की प्रेमिका ने भी आत्महत्या कर ली थी।

संत जेवियर्स कॉलेज के सेमिनार में स्टूडेंट्स को बताई गई अभिनय की कई बारीकियां

■ बाँडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन, कैमरा फेसिंग, सीन क्रिएशन और स्टोरीलाइन डेवलपमेंट जैसे विषयों पर दिया गया प्रशिक्षण

PHOTON NEWS RANCHI :

शनिवार को संत जेवियर्स कॉलेज में शनिवार को मॉडिया माईड्स के लिए अभिनय विषय पर एक दिवसीय एक्टिंग, फिल्म मेकिंग सह सेमिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग, एक्टर्स माईड एक्टिंग स्टूडियो और समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ, जिसमें 200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। वर्कशॉप के दौरान आकाश दीप ने अभिनय की बारीकियों को व्यावहारिक तरीके



कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों

फोटोन न्यूज

से समझाया। उन्होंने बाँडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन, कैमरा फेसिंग, सीन क्रिएशन और स्टोरीलाइन डेवलपमेंट जैसे विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। लाइव एक्टिंग ड्रिप्स और अभ्यास सत्रों के माध्यम से छात्रों ने न केवल सीखा बल्कि अपनी प्रतिभा को खुलकर प्रदर्शित भी किया। छात्रों ने इंटरैक्टिव सेशन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इंडस्ट्री से जुड़े अनुभवों को करीब से

समझा। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं आयोजकों ने बताया कि इस तरह के प्रोफेशनल वर्कशॉप छात्रों के कौशल विकास और करियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस आयोजन में विद्यार्थियों को अभिनय और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई दिशा, आत्मविश्वास और बेहतर अवसरों की समझ प्रदान की।

योजना

दो चरणों में पूर्ण होगी प्रक्रिया, पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगा सर्वे

झारखंड में जनगणना को लेकर विस्तृत और समयबद्ध शेड्यूल तय

PHOTON NEWS RANCHI :

केंद्र सरकार के निर्देश पर जनगणना 2027 को लेकर झारखंड सरकार ने विस्तृत और समयबद्ध शेड्यूल तय कर लिया है। राज्य में यह पूरी प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में 16 मई से 14 जून 2026 के बीच मकानों का सूचीकरण (हाउस लिस्टिंग) किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच पूरे देश के साथ-साथ झारखंड में भी व्यक्तियों की गणना की जाएगी। इस बार की जनगणना को पूरी तरह डिजिटल मोड में कराने पर विशेष जोर दिया गया है। गणनाकर्मियों को टैबलेट और मोबाइल एप उपलब्ध कराए

16 मई से 14 जून 2026 तक किया जाएगा मकानों का सूचीकरण

9 से 28 फरवरी 2027 के बीच चलेगा जनगणना का काम

पहले फेज में घर-घर सर्वे, 33 सवालों के जरिए जुटाया जाएगा डाटा

मई-जून 2026 के दौरान होने वाले मकान सूचीकरण में राज्य के सभी जिलों में घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान गणनाकर्मियों को 33 सवाल पूछे। इसमें मकान की स्थिति (कच्चा/पक्का), पेंशन की उपलब्धता, शौचालय, बिजली कनेक्शन, सोलर पैनल, टीवी, फ्रिज, वाहन (दो पहिया/चार पहिया), रसोई ईंधन, रसोईघर की संख्या जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, एक ही मकान में रहने वाले परिवारों की संख्या और उनकी प्रारंभिक जानकारी भी जुटाई जाएगी। इस संबंध में भूमि राजस्व एवं सुधार विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं और जिला स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।



प्रतीकात्मक फोटो

जाएंगे, जिनके माध्यम से डेटा सीधे ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत समयसीमा मांगी थी। झारखंड सरकार ने मौसम, प्रशासनिक तैयारी और क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह शेड्यूल तय किया है, ताकि प्रक्रिया सुचारु और प्रभावी ढंग से पूरी हो सके।

महिलाओं की भावनाओं का सियासी इस्तेमाल करना चाहती है भाजपा : सोनाल

RANCHI :

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सोनाल शांति ने केंद्र सरकार और भाजपा पर महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के परहेदारों ने लोकतंत्र को कलंकित होने से बचा लिया। उन्होंने कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के बजाय सरकार ने संशोधन के नाम पर परिसीमन विधेयक को प्राथमिकता दी, जो उसकी नीवत पर सवाल खड़े करता है। साथ ही कहा कि यदि केंद्र सरकार की मंशा साफ होती तो वर्तमान 543 लोकसभा सीटों में ही 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर 2024 के चुनाव में इसे लागू किया जा सकता था। इससे लोकसभा में करीब 180 महिला सांसद पहुंच सकती थीं।

आजसू ने रांची विश्वविद्यालय में की तालाबंदी, कहा-

विश्वविद्यालय केवल शैक्षणिक संस्था नहीं छात्रों की समस्या समाधान का भी है केंद्र

PHOTON NEWS RANCHI :

अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) ने रांची विश्वविद्यालय प्रशासन के छात्रों और छात्र प्रतिनिधियों से मिलने के समय को सीमित करने के निर्णय का विरोध करते हुए तुंगलकी फरमान फाड़कर विश्वविद्यालय में तालाबंदी की। आजसू ने इसे छात्रों के हितों के खिलाफ और दुर्भावपूर्ण निर्णय बताया। संघ ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शैक्षणिक संस्था ही नहीं, बल्कि छात्रों की समस्याओं के समाधान का प्रमुख केंद्र भी है। ऐसे में सवाल है कि वेवल शुक्रवार को एक घंटे का समय निर्धारित करना छात्रों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखने में बाधा उत्पन्न करेगा। अधिकतर छात्र दू-



दराज क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए सीमित समय में अपनी समस्याएं रखना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। आजसू ने कहा कि छात्र प्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि वे समय-समय पर छात्रों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएं। इस निर्णय के कारण संवाद प्रक्रिया बाधित होगी और विश्वविद्यालय में अस्थिर फैल सकता है। छात्र संघ ने प्रशासन से तुरंत इस निर्णय को वापस लेने की मांग की और प्रतिदिन छात्रों और छात्र प्रतिनिधियों को अपनी समस्याएं रखने की सुविधा देने की अपील की।

BRIEF NEWS

सारण पुलिस ने होटलों और बैंकों में चलाया सघन जांच अभियान

SARAN : वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों के होटलों एवं रेस्टोरेंट्स में औचक छापेमारी और जांच अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्रों का भौतिक सत्यापन किया और गैरस्टाफ के रजिस्ट्रारों एवं अन्य अभिलेखों की सुख्माता से जांच की। दूसरी ओर अपराध नियंत्रण एवं वित्तीय सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी के निर्देशन में सभी थानों द्वारा बैंक चेकिंग अभियान भी जारी है। पुलिस अधिकारी बैंकों में सुरक्षा उपकरणों, सीसीटीवी कैमरों और सख्त व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।

मांझी पुल से सरयू नदी में कूदी युवती को मछुआरों ने बचाया

SARAN : मांझी स्थित जयप्रभा सेतु पर शनिवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवती ने अचानक सरयू नदी की तेज धारा में छलांग लगा दी। पास में ही मछली पकड़ रहे मछुआरों ने युवती को नदी में गिरते देख मछुआरों ने अपनी नाव गहरे पानी की ओर मोड़ दी। कड़ी मशक्कत के बाद डूब रही युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही मांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोशी की हालत में युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों के मुताबिक युवती की स्थिति अब खतरे से बाहर है। युवती की पहचान मांझी नगर पंचायत के मियां पट्टी निवासी के रूप में हुई है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। मांझी थाना पुलिस ने बताया कि फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है आवेदन मिलने पर मामले की गहनता से जांच की जाएगी।

गर्मी को लेकर कई जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट

PATNA : बिहार में तापमान में हो रही लगातार वृद्धि से बड़ी गर्मी और खराब मौसम को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट 18 अप्रैल 2026 को रात 10:20 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान अचानक मौसम बिगड़ सकता है और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश तथा बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी और सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, चक्रपात (आकाशीय बिजली), तेज हवा और मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। खुले स्थानों, खेतों, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें, क्योंकि वज्रपात का खतरा अधिक रहता है।

विस सचिवालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई जानकारी विधानसभा का विशेष सत्र 24 को सम्पन्न चौधरी साबित करेंगे बहुमत

AGENCY PATNA : बिहार विधानसभा का दूसरा सत्र आगामी 24 अप्रैल 2026 को बुलाया गया है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र केवल एक दिन का होगा और सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि नई सरकार को इसी दिन सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आह्वान-पत्र में सभी विधायकों से समय पर सदन में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यवाही निर्धारित समय पर शुरू होगी और सभी सदस्यों को उपस्थिति अनिवार्य है।

इस विशेष सत्र में नई सरकार के गठन से जुड़े कई अहम कार्य पूरे किए जाएंगे। इसमें विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) का चुनाव, बहुमत परीक्षण और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं शामिल हैं। सम्पन्न चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र होगा, जिसमें वे सदन में मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी पहली बार इस भूमिका में नजर आएंगे।

सदन में विभिन्न दलों की स्थिति

■ भारतीय जनता पार्टी - 89, जनता दल (यूनाइटेड) - 85, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) - 19, हिंदुस्तानी अदाम मोर्चा - 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा - 4

■ कुल मिलाकर राजग को विभाग 201-202 विधायकों का समर्थन प्राप्त

■ विपक्षी महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल - 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस - 6, भाकपा (माले) - 2, भाकपा (मावसवादी) - 1, इंडियन इंकलुसिव पार्टी के 1 सदस्य

■ अन्य दलों में ऑल इंडिया मुजलिंस-ए-इतोहादुल मुस्लिमीन - 5 और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक

■ जानकारों का मानना है कि बिहार विधानसभा में संख्याबल के आधार पर राजग की नई सरकार मजबूत स्थिति में है और 24 अप्रैल को होने वाला बहुमत परीक्षण मात्र औपचारिकता है।



सीएम ऑफिस में मुख्यमंत्री सम्पन्न चौधरी

उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद 15 अप्रैल को सम्पन्न चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। संविधान और संसदीय परंपरा के अनुसार,

जब भी नई सरकार बनती है या मुख्यमंत्री बदलता है, तो उसे सदन में पलोर टेस्ट (बहुमत परीक्षण) के जरिए यह साबित करना होता है कि उसके पास विधायकों का पर्याप्त समर्थन है। बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122

विधायकों का समर्थन आवश्यक होता है। वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास स्पष्ट बहुमत है, जिससे सम्पन्न चौधरी सरकार को बहुमत साबित करने में किसी प्रकार की बाधा आने की संभावना कम है।

विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन आवश्यक होता है। वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास स्पष्ट बहुमत है, जिससे सम्पन्न चौधरी सरकार को बहुमत साबित करने में किसी प्रकार की बाधा आने की संभावना कम है।

गलगलिया चेकपोस्ट पर लग्जरी कार से 181.56 लीटर विदेशी शराब बरामद

AGENCY KISHANGANJ : उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को गलगलिया चेक पोस्ट के पास बड़ी कारवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 181.56 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों में पहचान मोहम्मद तौसीफ एवं चालक मोहम्मद मुल्लजिर के रूप में हुई है, जो अररिया जिले के जोकीहाट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार मिश्रा के निर्देश पर उत्पाद थानाध्यक्ष संगम कुमार विद्याधी के नेतृत्व में यह कारवाई की गई। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल के सिलौगुड़ी से शराब की बड़ी खेप किशनगंज के रास्ते ठाकुरगंज एवं गलगलिया होते हुए अररिया जिले के जोकीहाट ले जाई जा रही है।



सूचना के आधार पर उत्पाद टीम ने गलगलिया चेक पोस्ट एवं बंगाल सीमा से सटे मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी। इसी दौरान बंगाल की ओर से आ रही एक सख्त लज्जरी कार को रुकने का इशारा किया गया लेकिन चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश करने लगा। टीम ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। वाहन की तलाशी लेने पर 181.56 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। इसके बाद वाहन समेत दोनों आरोपियों को उत्पाद थाना लाया गया, जहां पुनः गहन तलाशी ली गई।

राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, निशांत को मिला 'जेड' क्लास सिक््योरिटी

AGENCY PATNA : राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश बिहार गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा शनिवार को जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गई है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही जदयू के विधायक और नीतीश कुमार के करीबी श्रवण कुमार को भी सुरक्षा दी गई है। जारी आदेश के अनुसार पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा श्रेणी में खास बढाव हुआ है। उन्हें पूर्व में 'जेड-' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिसे अब घटाकर 'जेड'



पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार

श्रेणी कर दिया गया है। इसके अलावा जदयू नेता निशांत कुमार को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। आदेश में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है, हालांकि पूर्व सुरक्षा स्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री श्रवण कुमार को भी अब जेड+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। यह श्रेणी अपेक्षाकृत मध्यम स्तर की सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है, जिसमें सशस्त्र एस्कॉर्ट की सुविधा शामिल रहती है। जारी पत्र में कहा गया है कि यह आदेश राज्य सुरक्षा समिति की 17 अप्रैल 2026 को हुई बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर जारी किया गया है। आदेश में कई प्रमुख राजनीतिक एवं सार्वजनिक व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणियों में संशोधन किया गया है, जिसे प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है।

जारी है, जिसमें सशस्त्र एस्कॉर्ट की सुविधा शामिल रहती है। जारी पत्र में कहा गया है कि यह आदेश राज्य सुरक्षा समिति की 17 अप्रैल 2026 को हुई बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर जारी किया गया है। आदेश में कई प्रमुख राजनीतिक एवं सार्वजनिक व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणियों में संशोधन किया गया है, जिसे प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है।

सरकारी कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर करना है जनगणना का काम : जिलाधिकारी

AGENCY SARAN : भारत की जनगणना को सटीक और पारदर्शी प्रक्रिया बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सारण समाहरणालय में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्वगणना को अनिवार्य अभियान बताते हुए जिले के सभी सरकारी कर्मियों को इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जितना अधिक स्वगणना किया जाएगा मुख्य जनगणना का कार्य उतना ही सरल, सटीक और पारदर्शी होगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों को प्रेरित करें। इसके साथ ही एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, आंगनबाड़ी सेविका-



पदाधिकारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव

सहायिका और टोला सेवकों के माध्यम से आम जनता के बीच जनजागरण चलाकर अधिक से अधिक लोगों को पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करने हेतु प्रोत्साहित करने को कहा। स्वगणना को गति देने के लिए जिलाधिकारी ने एक कंट्रोल रूम पोर्टल पर एचएलबी प्रोजेक्ट कर लिया जाए। 22 अप्रैल तक जियो टैगिंग और सीमांकन का कार्य हर हाल में पूर्ण हो।

चार्ज अधिकारियों को स्पष्ट किया कि 2 मई से शुरू होने वाले वास्तविक फील्ड कार्य से पूर्व प्रमाणक और सुरप्रवाइजर अपने क्षेत्रों में स्वगणना का कार्य सुनिश्चित कराएं। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आज संख्या तक सीएमएमएस पोर्टल पर एचएलबी प्रोजेक्ट कर लिया जाए। 22 अप्रैल तक जियो टैगिंग और सीमांकन का कार्य हर हाल में पूर्ण हो।

सूखा नशा न करने को लेकर युवाओं को किया गया जागरूक

NALANDA : नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल अंतर्गत आज शनिवार को समाजसेवी सह गुटखा छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आशुतोष कुमार मानव ने हिलसा बस स्टैंड के समीप शिक्षण संस्थानों में सूखा नशा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र युवाओं को नशा न करने का संकल्प दिलाया। इस दौरान इंगलिश कंपीटिशन जोन में उन्होंने कहा कि सूखे नशे के दलदल में फंसकर आज कल बड़ी संख्या में नौजवान बेमौत मारे जा रहे हैं वहां व्यापक पैमाने पर सूखा नशा का कारोबार बढ़ता जा रहा है। अगर समय रहते लोग नहीं चेते तो आने वाले समय में युवा शक्ति बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने युवाओं से नशा न करने की अपील की कि उन्होंने कहा कि नशा नशा की जननी है जो परिवार और समाज को भी खोखला कर देता है।

13 थाना क्षेत्रों से 55 मोबाइल बरामद, ऑपरेशन मुस्कान में किशनगंज पुलिस की बड़ी कारवाई

AGENCY KISHANGANJ : बिहार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत किशनगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 55 खोए, गुमसुद और चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामद मोबाइल की कुल कीमत लगभग 13 लाख 70 हजार रुपये बताई जा रही है। एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर सभी थाना के अपर थानाध्यक्ष एवं जिला आसूचना इकाई की संयुक्त टीम का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने आईएमईआई ट्रैकिंग, सीईआईआई ऑपरटल, तकनीकी विशेषण और आधुनिक तकनीक की मदद से मोबाइल फोन की



वास्तविक मालिकों को छोटा मोबाइल लौटाने के बाद पुलिस पदाधिकारी

बरामदगी की। पुलिस के अनुसार दिघलबैंक थाना क्षेत्र से 20, किशनगंज थाना से 6, कोचाधाम से 6, देहागाछ से 5, बहादुरगंज से 5, पहाड़कट्टा से 3, फतेहपुर से 2, गलगलिया से 2, अराबाड़ी से 2, बिबीगंज से 1, कोढ़ाबाड़ी से 1, चरनडगा से 1 तथा जियापौखर थाना क्षेत्र से 1 मोबाइल बरामद किया गया। बरामद मोबाइल फोन में आईफोन, वन प्लस, रियलमी, वीवो, ओपो, सैमसंग गैलेक्सी, पोको, रेडमी, टेकनो, आईटेल और

मोटोरोला कंपनी के मोबाइल शामिल हैं। सभी बरामद मोबाइल पुलिस कार्यालय किशनगंज में आयोजित कार्यक्रम में वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। मोबाइल मिलने पर लाभार्थियों ने पुलिस के प्रति आभार जताया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि बरामदगी अभियान में शामिल जिला आसूचना इकाई और संबंधित थाना के अपर थानाध्यक्षों को पुरस्कृत किया जाएगा।

अच्छी पहल

5 लाख 'प्लास्टिक वॉरियर्स' तैयार करने का लक्ष्य

पृथ्वी दिवस पर चलाया जाएगा ऐतिहासिक पर्यावरण अभियान

AGENCY SUPAUL : पृथ्वी दिवस 2026 के अवसर पर बिहार में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक जन-अभियान की शुरुआत की गई है। 15 अप्रैल से 31 मई तक चलने वाले इस राज्यव्यापी अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने और उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है।



प्रतीकात्मक फोटो

अधिक विद्यालयों में 5 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं, स्काउट और गाइड को ह्यूमनाइस्टिक वॉरियर्स के रूप में तैयार किया जाएगा। ये छात्र अपने-अपने विद्यालय, परिवार और समाज में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पर्यावरण संरक्षण के उपाय

अपनाने तथा लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस पहल का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं को जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करना भी है। सुपौल जिले में इस अभियान का

नेतृत्व भारत स्काउट और गाइड के जिला संगठन आयुक्त सह जिला प्रशिक्षण आयुक्त श्री संजय कुमार झा कर रहे हैं। सुपौल अनुमंडल में अमन कुमार, त्रिवेणीगंज अनुमंडल में सोरब सुमन, वीरपुर अनुमंडल में कोशिक वत्स तथा निर्मली

अनुमंडल में देवेन्द्र कुमार इस अभियान को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत विद्यालयों में पौधारोपण कर हरित परिसर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जाएगा। गांव और शहरों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास जैसे विषयों पर पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

छपरा में कल सोलर लोन मेला का किया जाएगा आयोजन

SARAN : जिला प्रशासन एवं विद्युत आपूर्ति अंचल के तत्वावधान में आगामी 20 अप्रैल 2026 को छपरा के भिखारी ठाकुर गृह में एक सोलर लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को धरातल पर उतारना है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव होंगे। इस मेले की विशेषता यह है कि ऑन-द-स्पॉट विभिन्न बैंकों के स्टॉल के माध्यम से उपभोक्ताओं को सोलर पैनल हेतु आसान किस्तों और आकर्षक ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराएंगे।

बापू की विचारधारा को फिर से जन-जन तक पहुंचाएंगे : राजेश राम

AGENCY PATNA : सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के तीन दिवसीय 'सर्वोदय संकल्प शिविर' का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर शिविर में प्रशिक्षण ले रहे कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आज ऐसे समय में यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जब देश में महात्मा गांधी की विचारधारा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बापू के सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के सिद्धांतों को समाज के बीच फिर से मजबूत करने के उद्देश्य से इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर



आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह शिविर कार्यकर्ताओं को गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप जीवन शैली और कार्यशैली सीखाने के लिए आयोजित किया गया है। इस शिविर के माध्यम से कार्यकर्ता गांधीवादी की भावना को समझेंगे और समाज में उसे लागू करने की दिशा में कार्य करेंगे। राजेश राम ने कहा कि वर्तमान सरकार जिस प्रकार से महात्मा गांधी के विचारों और मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, वह अत्यंत दुःखद और चिंताजनक है।

किसानों की समृद्धि और मध्य प्रदेश की प्रगति

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को अन्नदाता के साथ-साथ ऊजादाता बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प की देन 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की ऐतिहासिक घोषणा है। यह मिशन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसान परिवारों के जीवन को संवारने, उनकी आय दोगुनी करने और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक विजयनी संकल्प है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के उत्थान को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए धरातल पर उन्होंने कई ठोस कदम उठाए हैं। डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से वर्ष 2026 मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित होगा। मुख्यमंत्री की किसान केन्द्रित नीतियां व्यावहारिक और दूरदर्शी हैं। सरकार ने मिशन ज्ञान के अंतर्गत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी है। अप्रैल 2025 में कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन को मंजूरी दी जिसका मुख्य लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना, जलवायु अनुकूल और सतत कृषि को बढ़ावा देना जैविक खेती, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना है। खेती का रकबा 2.50 लाख हेक्टेयर बढ़ाने, तीन नदी जोड़ो परियोजना से 16 लाख हेक्टेयर सिंचाई, माहक्रो इरीगेशन विस्तार, आधुनिक मंडियां, बीज परीक्षण लैब और फसल नुकसान सर्वे के लिए तहसील स्तरीय मौसम केन्द्र जैसी रोडमैप में किसानों का मन मोह लिया है। भावांतर योजना का विस्तार कर सोयाबीन के बाद सरसों को शामिल किया गया, जबकि उड़द और मूंगफली पर समर्थन मूल्य के साथ बोसम दिए जाने की बड़ी घोषणा भी हुई। मुख्यमंत्री किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं। किसानों के हितों में लिए जा रहे अनेक निर्णय न केवल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि सरकार की किसान कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री की भावांतर राशि की घोषणा से किसानों के चेहरे पर नई आशा, उत्साह और विश्वास का संचार हुआ है। सीएम के विजन से मध्यप्रदेश में कृषि विकास योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार योजनाओं की पहुंच परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। मध्यप्रदेश को देश का इकलौता राज्य है जहां किसानों को 5 रुपये में बिजली कनेक्शन (कामधेनु) स्थापना नीति-2025हू लागू की है। इसके तहत 5000 से अधिक गांवों वाली बड़ी आत्मनिर्भर गोशालाएं स्थापित करने की योजना है। गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली और भूसे की मशीनों उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में प्रदेश में दूध संग्रहण की काफी बढ़ चुका है। सरकार ने शासकीय गोशालाओं में प्रति गाय अनुदान राशि बढ़ाई है और पशुधन रखने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। प्रदेश में अब तय वक्त पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी किये जाने पर सहमति बन चुकी है। उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले सभी किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। गेहूं उपार्जन में बारदान की उपलब्धता निरंतर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार, जूट कमिश्नर सहित अन्य बारदान प्रदाय एजेंसियों से बारदान आपूर्ति के लिए राज्य सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है। कमिश्नर और कलेक्टरों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने समग्र किसान कल्याण पर जोर दिया है। पशुपालन, मत्स्य विकास और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मोहन सरकार तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश के 19 लाख 4 हजार 644 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से एवं अन्य सभी संभागों में 15 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन प्रारंभ होने जा रहा है। गेहूं उपार्जन के लिए इस वर्ष प्रदेश में कुल 3627 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। बीते उपार्जन वर्ष 2025-26 में 15 लाख 44 हजार 55 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया था। इस उपार्जन वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,625 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनास का लाभ भी इस वर्ष देने जा रही है। किसानों का जीवन संवारने और इनकी बेहतरी के लिए पूर्ण समर्पित भाव से मिशन मोड में कृषि वर्ष का प्रभावी क्रियाच्यवन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों को वैश्विक वर्ल्ड क्लास मंडी की तर्ज पर अपग्रेड किया जाना चाहिए। सीएम ने स्पष्ट कहा कि किसानों की समृद्धि ही उनकी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। उनका यह दृष्टिकोण न केवल मध्यप्रदेश को कृषि प्रधान राज्य के रूप में स्थापित करेगा, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर देश के विकास में योगदान देगा। निश्चय ही मध्यप्रदेश के किसानों के लिए वर्ष 2026 किसान कल्याण की नई इबारत लिखने वाला साबित होगा।

ANALYSIS



विनोद कुमार सिंह

ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक जिस प्रकार मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, वह इस बात का द्योतक है कि मतदाता अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग और सचेत हैं। यह उत्साह जहां एक ओर सत्तारूढ़ दल के लिए नुनौती का संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर यह भी दर्शाता है कि यदि सरकार ने अपने कार्यों से जनविश्वास अर्जित किया है, तो उसे पुनः अवसर भी मिल सकता है। केरल का मतदान प्रतिशत अपनी प्रकृति में भले ही संतुलित प्रतीत होता हो, लेकिन उसकी गहराई में एक परिपक्व लोकतांत्रिक चेतना का प्रवाह दिखाई देता है। यहां का मतदाता परंपरागत रूप से विचारधारा आधारित मतदान करता है और यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत स्थिर रहते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत देता है। लगभग 78 प्रतिशत मतदान यह बताता है कि केरल में लोकतंत्र केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक वैचारिक अभ्यास है, जिसमें हर मतदाता अपने निर्णय को एक जिम्मेदारी के रूप में देखता है। पुडुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास मतदान ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र का प्रवाह हर क्षेत्र में एक परिपक्व लोकतांत्रिक चेतना का प्रवाह दिखाई देता है। यहां का मतदाता परंपरागत रूप से विचारधारा आधारित मतदान करता है और यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत स्थिर रहते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत देता है। लगभग 78 प्रतिशत मतदान यह बताता है कि केरल में लोकतंत्र केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक वैचारिक अभ्यास है, जिसमें हर मतदाता अपने निर्णय को एक जिम्मेदारी के रूप में देखता है। पुडुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास मतदान ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र का प्रवाह हर क्षेत्र में एक परिपक्व लोकतांत्रिक चेतना का प्रवाह दिखाई देता है। यहां का मतदाता परंपरागत रूप से विचारधारा आधारित मतदान करता है और यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत स्थिर रहते हुए भी अत्यंत

हमारा लोकतंत्र केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जनचेतना की वह जीवंत धारा है, जो समय-समय पर अपने स्वरूप, अपने तेवर और अपनी दिशा को स्वयं निर्धारित करती है। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों का प्रथम चरण असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में संपन्न मतदान इसी लोकतांत्रिक चेतना का प्रखर और व्यापक प्रतिबिंब बनकर सामने आया है। यह चरण ईवीएम मशीनों तक सीमित एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनमत की वह गुंज है, जिसमें सामाजिक परिवर्तन की आहट, राजनीतिक पुनर्संतुलन की छाया और भविष्य की राजनीति की स्पष्ट रूपरेखा सुनाई देती है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों ने इस लोकतांत्रिक उत्सव को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। असम में लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मतदान, केरल में लगभग 78 प्रतिशत और पुडुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास मतदान ने यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत का मतदाता अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय और निर्णायक भागीदार बन चुका है। यह आंकड़े केवल प्रतिशत नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास, उसकी प्रतिबद्धता और उसकी आकांक्षाओं का जीवंत प्रमाण हैं। असम में उच्च मतदान यह संकेत देता है कि यहां चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनसरोकारों की अभिव्यक्ति का मंच बन चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक जिस प्रकार मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, वह इस बात का द्योतक है कि मतदाता अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग और सचेत हैं। यह उत्साह जहां एक ओर सत्तारूढ़ दल के लिए नुनौती का संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर यह भी दर्शाता है कि यदि सरकार ने अपने कार्यों से जनविश्वास अर्जित किया है, तो उसे पुनः अवसर भी मिल सकता है। केरल का मतदान प्रतिशत अपनी प्रकृति में भले ही संतुलित प्रतीत होता हो, लेकिन उसकी गहराई में एक परिपक्व लोकतांत्रिक चेतना का प्रवाह दिखाई देता है। यहां का मतदाता परंपरागत रूप से विचारधारा आधारित मतदान करता है और यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत स्थिर रहते हुए भी अत्यंत



महत्वपूर्ण संकेत देता है। लगभग 78 प्रतिशत मतदान यह बताता है कि केरल में लोकतंत्र केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक वैचारिक अभ्यास है, जिसमें हर मतदाता अपने निर्णय को एक जिम्मेदारी के रूप में देखता है। पुडुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास मतदान ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र का उत्साह क्षेत्रफल या जनसंख्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जनभागीदारी की भावना पर आधारित होता है। छोटे से केंद्र शासित प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का मतदान करना यह दर्शाता है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। यह मतदान न केवल राजनीतिक दलों के लिए संदेश है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी है कि लोकतंत्र की असली शक्ति जनता की सक्रिय भागीदारी में निहित है। इस प्रथम चरण का एक और महत्वपूर्ण पक्ष मतदाता संरचना में हो रहा परिवर्तन है। लगभग 5.3 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि लोकतंत्र अब केवल संख्याओं का खेल नहीं, वरन विविधता और समावेश का उत्सव बन चुका है। महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या और उनकी सक्रिय भागीदारी इस परिवर्तन का सबसे सशक्त संकेत है। केरल और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर या उससे अधिक होना केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का संकेत है। महिलाएं अब केवल मतदान करने वाली इकाई नहीं, बल्कि नीति निर्धारण को प्रभावित करने वाली शक्ति बन चुकी हैं। उनके मुद्दे अब चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं चाहे वह महंगाई हो, स्वास्थ्य

सेवाएं हों, शिक्षा हो या सुरक्षा। राजनीतिक दलों ने भी इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है और महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं और घोषणाएं प्रस्तुत की हैं। यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में महिला मतदाता भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। युवा मतदाताओं की भागीदारी इस चुनाव की आत्मा है। लाखों नए मतदाताओं का पहली बार मतदान करना यह दर्शाता है कि भारत का भविष्य अब मतदान केंद्रों तक पहुंच चुका है। यह युवा वर्ग पारंपरिक राजनीति से अलग सोच रखता है। उसके लिए जातीय या धार्मिक समीकरणों की अपेक्षा रोजगार, शिक्षा, डिजिटल अवसर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा अधिक महत्वपूर्ण हैं। वह केवल वोटों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि परिणाम चाहता है, पारदर्शिता चाहता है और अवसर चाहता है। यही कारण है कि आज की राजनीति में युवाओं की भूमिका केवल सहायक नहीं, बल्कि निर्णायक बन चुकी है। पुरुष मतदाताओं की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन महिला और युवा मतदाताओं के उभार ने चुनावी समीकरणों को अधिक संतुलित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। यह परिवर्तन लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इससे चुनाव अधिक निष्पक्ष और परिणाम अधिक प्रतिनिधिक बनेंगे हैं। अगर हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो असम, केरल और पुडुचेरी तीनों ही क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। असम में जहां भाजपा नेतृत्व

वाले गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, वहीं केरल में पारंपरिक एलडीएफ और युडीएफ के बीच वैचारिक संघर्ष है। पुडुचेरी में त्रिकोणीय मुकाबला चुनाव को और अधिक जटिल और रोचक बना रहा है। असम में उच्च मतदान यह संकेत देता है कि चुनाव अत्यंत प्रतिस्पर्धी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सत्तारूढ़ गठबंधन अपने लाभार्थी वर्ग और महिला मतदाताओं का समर्थन बनाए रखने में सफल रहता है, तो उसे बढ़त मिल सकती है, लेकिन उच्च मतदान अक्सर सत्ता विरोधी भावना का संकेत होता है, जिससे चुनाव परिणाम अनिश्चित हो जाता है। केरल में स्थिति और भी जटिल है, क्योंकि वहां का मतदाता अत्यंत जागरूक और वैचारिक है। यहां चुनाव परिणाम बहुत ही सूक्ष्म अंतर से तय होते हैं और यही कारण है कि दोनों प्रमुख गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में हैं। पुडुचेरी में रिक्तों मतदान यह संकेत देता है कि मतदाता परिवर्तन चाहता है या स्पष्ट जनसंदेश देना चाहता है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के कारण यहां हंग असेंबली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मतदान प्रतिशत के भीतर छिपे राजनीतिक संकेतों को यदि समझा जाए कि उच्च मतदान केवल संकेत नहीं, बल्कि एक संदेश है। यह संदेश कभी बदलाव का होता है, कभी समर्थन का और कभी संतुलन का। महिला मतदाताओं की सक्रियता यह दर्शाती है कि कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा अब राजनीति के केंद्र में हैं। युवा मतदाताओं की भागीदारी यह बताती है कि भविष्य की राजनीति विकास और अवसरों के इर्द-गिर्द घूमेगी। प्रथम चरण का यह मतदान यह भी स्पष्ट करता है कि भारतीय लोकतंत्र अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। यह दौर परंपरागत समीकरणों से आगे बढ़कर विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित है। मतदाता अब केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, वरन अपने अनुभव और अपेक्षाओं के आधार पर निर्णय लेता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 2026 के विधानसभा चुनावों का प्रथम चरण केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक आत्मविश्वास का सशक्त प्रमाण है।

एनर्जी संकट से क्यों जूझ रहा भारत

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद सारी दुनिया के देशों में जिस तरह से एनर्जी संकट देखने को मिल रहा है, वह अपने आप में भयाक्रांत करने वाली स्थिति है। भारत अपनी ऊर्जा की लगभग 85 फीसदी जरूरतें आयात से पूरा करता है। भारत बड़ी मात्रा में खाद का आयात भी कर रहा है। चीन को भी भारी मात्रा में कच्चे तेल और गैस की जरूरत होती है। चीन पिछले कई वर्षों से कोयले के माध्यम से जिस तरह से अपनी ऊर्जा की जरूरत को लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस संकट में चीन ने अपने आप को किस तरह से बचाकर रखा है। भारत क्यों नहीं अपने आप को बचा पाया। इसका विश्लेषण करना जरूरी है। भारत चीन एवं अन्य देशों से खाद का आयात करता है। भारत को खाद संकट से जूझना पड़ रहा है। ऊर्जा संकट होने के बाद भी चीन अपनी जरूरत और निर्यात करने के लिए

खाद का उत्पादन किस तरह से कर पा रहा है। यह जानने की भारत सरकार को जरूरत है। चीन के पास गैस फोल्ड ना के बराबर है। इसके बाद भी वह कोयला से गैस बनाने का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। पिछले वर्षों में चीन ने इस क्षेत्र में तकनीकी और पूंजी में बड़ा निवेश किया है। चीन 80 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष एमएमटीपीए गैस का उत्पादन कर रहा है। भारत चीन के मुकाबले में मात्र 3.5 फीसदी ही कोयले से गैस बना पा रहा है। कोयला चीन और भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत अपने कोयले से गैस का उत्पादन बड़े पैमाने पर कर सकता था। भारत ने इस पर ना तो ध्यान दिया, ना ही इस तरह की नीतियां बनाईं देश पर हमारे पास जो संसाधन हैं उसका हम उपयोग कर पा रहे हैं। चीन की तुलना में भारत बुरी तरह से पिछड़ गया है। भारत सरकार और नीति आयोग की वेबसाइट हैं। उसके अनुसार कोयला से गैस उत्पादन की सात

से मीथेन गैस बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की थी। रानीगंज में एक छोटा पायलट संयंत्र शुरू किया गया था, उसके बाद भारत सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण भारत मीथेन गैस के उत्पादन में बुरी तरह से पिछड़ गया है। मोदी सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। 2020 में मोदी सरकार ने नेशनल कोल गैसीफिकेशन के काम की शुरुआत की। 2030 तक इसमें 100 एमएमटीपीए कोल के इस्तेमाल से गैस उत्पादन का लक्ष्य बनाया गया था। इसके लिए चार लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना था। इस योजना के लिए पिछले वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, जिसे संतोषपद कहा जा सके। पिछले 6 वर्षों में इस योजना में कुल 5 एमएमटीपीए का ही हम उपयोग कर पा रहे हैं। चीन की तुलना में भारत बुरी तरह से पिछड़ गया है। भारत सरकार और नीति आयोग की वेबसाइट हैं। उसके अनुसार कोयला से गैस उत्पादन की सात

परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी है। इसमें 64000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव में मंजूरी दी गई। यह सारी योजनायें सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर शुरू की जानी थी। इस मंजूरी के बाद भी कोयला और पर्यावरण मंत्रालय में आपसी विवाद के कारण इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। निजी क्षेत्र की कंपनी अदानी पावर का भी इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर्हीं ना कर्हीं कोई प्रभाव देखने को मिलता है। जिसके कारण इन परियोजनाओं पर जिस तेजी के साथ जो काम होना था, वह नहीं हो पा रहा है। चीन अपनी दूरदर्शिता से भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परियोजना तैयार करता है। इसके लिए पूंजी के साथ-साथ नवीनतम तकनीकी के रिसर्च और परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने में जी-जान लगा दी जाती है। भारत सरकार इस मामले में चीन के मुकाबले

कहीं खड़ी हुई नजर नहीं आती है। आज जिस तरह से ऊर्जा का संकट देखने को मिल रहा है, यदि हम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को भारत में भी बड़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। भारत सरकार ने जो नियम कानून का मकड़जाल बिछा कर रखा हुआ है, उसको साफ करते हुए यदि प्राथमिकता के साथ ऊर्जा संकट से निपटने के लिए हम वैकल्पिक संस्था संसाधनों की ओर काम करेंगे, तो कुछ ही वर्षों में काफी हद तक हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को स्वयं पूरा कर पाएंगे। डईएमोनिया फास्फेट के लिए अमोनिया जरूरी होता है। भारत अमोनिया का अभी बड़ी मात्रा में आयात कर रहा है। देश में इसकी भारी कमी है, जिसके कारण किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं भारत सरकार को इसके लिए विदेशी मुद्रा भी बड़े पैमाने पर खर्च करनी पड़ रही है। चीन द्वारा

दुनिया की पूरी जरूरत का 40 फीसदी यूरिया, कोयले से हासिल किए जाने वाली सिंथेटिक गैस के द्वारा उत्पादित की जा रही है। इसके अलावा चीन दुनिया को जरूरत के मिथानोल का 54 फीसदी उत्पादन कर पा रहा है। चीन हर उस चीज में निवेश कर रहा है, जिसमें चीन का आयात कम हो, निर्यात में वृद्धि हो। कोयले का जितना अच्छा उपयोग चीन कर पा रहा है, भारत के पास पर्याप्त कोयले का भंडार होने के बाद भी हम अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। परंपरागत रूप से अभी भी कोयला का उपयोग भारत पावर प्लांट को चलाने और औद्योगिक जरूरतों के लिए कर रहा है। भारत सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। भारत सरकार को तकनीकी के विकास की ओर भी ध्यान देना होगा। समय पर सारे कार्य हों। इस दिशा में कार्य किया गया, तो आने वाले कुछ ही वर्षों में विदेशी निर्भरता में भारी कमी आ सकती है।

Social Media Corner

सब के हक में...

मोदी-शाह ने देश की आधी आबादी को ढाल बनाकर हदबंदी करने की कोशिश की और इस देश के लोकतंत्र, सवधान और संवैधानिक को घोट पहुंचाने का दृष्टिकोण प्रयास किया। उनकी ये चालबाजी एकजुट विपक्ष- 'इंडिया' ने भींग ली और सविधान संशोधन बिल गिर गया। हम सभी विपक्षी दलों के नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मोदी-शाह अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भारत के लोकतंत्र को तबाह करने वाले थे, उनकी ये साजिश अब अधी मुह गिर गई है। हम मोदी सरकार से फिर एक बार मांग करते हैं कि वो 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के अनुसार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के चुनावों से ही दिया जाए। कांग्रेस पार्टी सितंबर 2023 से इसकी मांग कर रही है। यह 'नारी शक्ति' के प्रति प्रणामंत्री जी की प्रतिबद्धता की असली परीक्षा होगी।

(मल्लिकार्जुन खड़गे का 'एक्स' पर पोस्ट)

झारखंड में आईएसएफ आर्मीएसए अधिकारियों की ट्रांसफर पॉरिटिंग सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित वसूली उद्योग है। मुख्यमंत्री के संरक्षण में शीर्ष अधिकारियों, सत्ताधारी दलों के नेताओं और दलाल विधिलियों के सांठगाढ़ से इस वसूली को अंजाम दिया जाता है। आईएसए आर्मीएसए अधिकारियों की ट्रांसफर पॉरिटिंग में वसूली का खेल होने से उनके मातहत काम करने वाले अधिकारी भी भ्रष्टाचार को बाध्य या प्रेरित हो जाते हैं। यदि राज्य सरकार ने इस बार पारदर्शिक के साथ ट्रांसफर पॉरिटिंग की है तो यह अच्छी बात है। हमारी मांग है कि सरकार को यदि वसूली गैस से सम्बन्धित जानकारी मिली है तो उनके नाम सार्वजनिक करें, ताकि राज्य के ईमानदार और होनहार अधिकारी भी सरकारी दयतारों के आसपास मंडराने वाले दलाल-विधिलियों के गंगुल से खुद को बचा सकें।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)



अशांति की आग में कब तक झुलसता रहेगा मणिपुर

मणिपुर फिर जल उठा है। मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है और यह केवल एक राज्य का संकट नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुका है। लोकसभा में पटल से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मणिपुर में जल्द ही शांति का सूरज जरूर उगेगा। उनके उस बयान पर उस समय सदन में ज्यादातर सांसदों ने मेज थपथपा कर अपना समर्थन दिया था। पीएम मोदी की आवाज में भी एक ऐसा विश्वास था कि सभी मान गए थे कि मणिपुर में हालात सुधर जाएंगे। अब उस बयान को दो साल पूरे होने को है और मणिपुर फिर जल रहा है, मणिपुर फिर कर्ण्यू का दंश झेल रहा है, कई जगहों पर इंटरनेट सस्पेंड हो चुका है। केन्द्र और राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। मोहरांग क्षेत्र में हुए रॉकेट हमले में दो मासूम बच्चों की मौत ने इस संकट को और भयावह बना दिया है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा ने हालात को तनावपूर्ण बना दिया है। ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की फायरिंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। वहीं राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं में आंशिक राहत देने का फैसला किया है, ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों। मणिपुर में हालिया हिंसा के दौरान सुरक्षा बल की फायरिंग में घायल

हुए एक युवक की बुधवार को मौत हो गई। मृतक को पहचान 31 वर्षीय वांगंहगबम बॉबी के रूप में हुई है। वह बिष्णुपुर जिले के कुंबी तेलखोंग माखा लोकाई का रहने वाला था। इस मौत के बाद फायरिंग में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। इससे पहले दो लोगों की जान गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। यह घटना सिर्फ एक आतंरिक वारदात नहीं, बल्कि उस अस्थिर सामाजिक ढांचे का प्रतीक है, जो पिछले कई महीनों से भीतर ही भीतर सुलग रहा था। इस दर्दनाक घटना ने न केवल स्थानीय लोगों के मन में भय और आक्रोश पैदा किया है, बल्कि पूरे देश के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर मणिपुर में में शांति कब और कैसे लौटेगी। इस प्रदेश में स्थायी शांति का इंतजार काफी लंबा होता जा रहा है। रात के सन्नाटे में एक घर पर रॉकेट हमला होना, जिसमें एक पांच महीने की बच्ची और एक पांच साल के बच्चे की जान चली जाती है, यह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक और अस्वीकार्य है। यह आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उन परिवारों की दृष्टि दुनिया की कहानी है, जिनके लिए जीवन का कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। बिष्णुपुर जिले में इस घटना के बाद जो प्रतिक्रिया देखने को मिली, वह इस बात का संकेत है कि जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है। सड़कों पर उत्तरी भौड़, कर्ण्यू का लागू होना, पांच जिलों में इंटरनेट

सेवाओं का बंद होना और सुरक्षा बलों की बढ़ती तैनाती ये सभी हालात की गंभीरता को दर्शाते हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक प्रतिक्रिया और जवाब में हुई फायरिंग, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, यह बताता है कि हालात कितने नाजुक और विस्फोटक हो चुके हैं। मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा का यह नया अध्याय है, जिसकी जड़ें कहीं गहरी हैं। मैतैई और कुकी को समुदायों के बीच बढ़ती दूरी और अविश्वास ने इस संघर्ष को लगातार हवा दी है। 27 मार्च 2023 को हाई कोर्ट के उस निर्देश के बाद, जिसमें मैतैई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने की बात कही गई थी, स्थिति और भी संवेदनशील हो गई। कुकी और अन्य आदिवासी समुदायों को यह डर सताने लगा कि उनके अधिकारों और संसाधनों पर असर पड़ेगा। इसके बाद 3 मई 2023 को शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे हिंसा में बदल गया और आज तक यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती, कर्ण्यू, इंटरनेट सेवाओं का निलंबन, शांति समिति का गठन और राहत शिविरों का संचालन ये सभी प्रयास इस बात का संकेत हैं कि प्रशासन स्थिति को संभालने के लिए सक्रिय है। लेकिन, इसके बावजूद हिंसा का दौर जारी है।

चंचल मन

लंबे समय से साहब के चेले का मन सादी दाल खाकर उचाटे लेकर, संन्यासी हो रहा था। उसने डरते डरते पत्नी से बचारी हुई दाल परोसने का आग्रह विनम्रता पूर्वक किया। पत्नी के लाल फैले हुए चबुडों से भयभीत हो स्वयं को समेटते हुए चेले ने लगभग धिंधियाते हुए दाल बघारने में श्रद्धा शब्द का संशोधन किया। समय एवं सामग्री की उपलब्धता और श्रद्धानुसार ही बचारी दाल परोसने का पुनः आग्रह का प्रयास किया। आती हुई संक्रांति की कुनकुनी धूप की तरह तनिक सी पिघली धर्मपत्नी ने यथासंभव बचारी दाल परोसकर विजयी मुस्कान के साथ किटी पार्टी की ओर बिना अनुमति रख किया। घर में होती दैनिक दुर्दशा के परे बचारी दाल के चटखारे लेकर प्राप्त ऊर्जा से अपने दिन को आलौकिक करने चेले भाई, अपने ठीहा पर पहुंच कर साहब के कदमों में दंडवत हुए। उन्होंने अंगूठे के नाखून का स्पर्श कर स्वयं को कुतार्थ किया। अपने वैज्ञानिक नजरिए से पेशीय बल द्वारा साहब की पेशियों का अंगुलियों से मसलान आरंभ किया। यहां स्मरण रहे पेशीय बल एवं गति के साथ मुखारविंद से अमूल नवनीत का झरना भी द्रुतगति से गतिमान था। हाथ ज्योंही घुटने पर पहुंचे बुद्धि का ज्वालामुखी फट पड़ा। हुजूर, आपके कार्यों की संख्या से सारा गांव पटा पड़ा है, किंतु आज तो सभी वाह-वाह में हैं, लेकिन लंबे समय की वाह की गारंटी पौरियड कब वारंटी में बदल जाए, पता नहीं। कोई अविस्मरणीय प्रयास हो तो काम के साथ नाम भी अमित रहे, मेरे भतीजे की नई दुकान में शिलालेख नूतन तकनीक से बन रहे हैं कहे तो बात बलाऊ, किंतु साहब मेरी सोच है किये दो प्रकार से बनें, एक में नाम बड़ा, किसी में काम बड़ा। हुजूर पब्लिक आब्जेक्शन करें तो कहिएगा लोगों को नाम बड़ा का बनवाया था, लेकिन साहब ने कहा किसी काम बड़ा होता है, नाम नहीं। इसलिए काम बड़ा का बनवाया। इस तरह गांव में दोनों प्रकार से नाम होगा, सहदयता का भी प्रसार होगा कि साहब काम को नाम से बड़ा मानते हैं।

Women's credit access: To ensure borrowing means building

A new report, titled From Borrowers to Builders, presents numbers that, at first glance, should be cause for celebration. The study by TransUnion Cibil, Niti Aayog and MicroSave says Indian women now hold a formal credit portfolio worth ₹76 lakh crore—a 4.8-fold increase since 2017, outpacing the 2.9-fold growth recorded for borrowers overall. Credit penetration among women has risen from 19 percent in 2017 to 36 percent to 2025. Women with active business loans have grown at a 31 percent compound annual rate over the past three years, nearly double the pace of overall commercial credit.

However, once you move past the numbers, a more complicated picture emerges—one that raises a question the report points toward but does not quite answer: credit for what, exactly? And on whose terms? Consider the composition of first loans. As women enter the formal credit sector, their borrowings are not for business investment or education. Comprising gold loans, consumer durables and personal loans, such first-time formal credit finances consumption. While not undesirable in themselves, these are the products financial systems find easiest to sell to women—low-ticket, collateral-backed and tied to household expenditure rather than enterprise ambition. The report notes housing finance is one secured category where women show rising participation. However, much of this is as co-applicants, riding on a husband's or father's application to access stamp duty concessions. Is that financial inclusion or financial adjacency? The report also highlights the microfinance segment's attempts at inclusion. For two decades, joint-liability group lending to women from low-income households has been held up as the gold standard of inclusive finance. It has genuinely lifted millions. However, faced with over-indebtedness and rising non-performing assets, lenders have turned to existing borrowers rather than expanding the base. The share of first-time women borrowers in microfinance originations has slipped from 28 percent in 2022 to 24 percent in 2025. Expanding financial inclusion requires widening the system, not merely deepening it. The report's most valuable—yet most unsettling—section is its field research among rural women nano-entrepreneurs in Kerala and Madhya Pradesh running tiny businesses, owning smartphones and with 60-70 percent accepting digital payments. By standard metrics, the recorded 161 women entrepreneurs are digitally included. However, the researchers find that digital access is not the same as digital agency. Transactions are often assisted by family members. Decisions over credit, pricing and procurement are frequently not the woman's own.

In Kerala, 38 percent of women entrepreneurs reported 'time poverty'—the double burden of running a business while managing a household—as the principal barrier to sustained digital engagement.

This points to a structural problem no amount of UPI adoption can fix on its own. India's formal economy has historically been built around a model of the economically visible citizen—someone with a salary slip, a tax record or a provident fund account. Women running nano-enterprises out of their homes, trading in cash and embedded in informal networks have never fit that model. Digital finance has helped, but the report is candid that women's digital footprints are often thin, inconsistent and interrupted. Three things actually need to change. First, lenders and policymakers must stop treating access as the finish line. Nearly two-thirds of credit-eligible Indian women still have no formal loan. Of those who do, nearly half have held only a single product in their lifetimes. The report recommends tracking graduation rates, multi-product holding and enterprise growth rather than raw disbursement volumes. While these initiatives may make the numbers suddenly look unimpressive and politically undesirable, these are what need to be measured.

Women's Reservation shouldn't be linked to distraction of delimitation

If the Nari Shakti Vandan Adhiniyam were to be linked to population counts, it would give women's reservation up to 48-49% which is their demographic share, not 33%

In all the din of rising debate on women's reservation in the run up to the Special Session of Parliament that begins today (April 16-18), one core point is being clouded over. Women's reservation is not linked to the Census and delimitation. If it was linked to population counts, it would give women's reservation up to 48-49%, which is their demographic share. Since the 2023 Act reserves 33% instead, it can be implemented at any time. The government's attempt to tie women's reservation to an increase in seats and fresh delimitation in the Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026, is therefore wrong. More worrying still, the Bill erases the link between seats' expansion and the Census, suggesting that a new Delimitation Commission be told to draw boundaries for 815 electoral constituencies. How can a decision on the number of total Lok Sabha seats be taken without a population count? Even more pertinently, how can 815 constituencies be drawn without a population count?

The government's answer is to use the 2011 Census since the ongoing Census's results will only be available in 2028-2030, too late for delimitation before the 2029 elections. But the Constitutional changes proposed in the Bill leave it entirely to any party in office to decide the strength and composition of the legislature. That is very dangerous. Since the government delayed beginning the Census until 2026, we are being told that it is better to simply accept an arbitrary figure decided upon by the ruling party, with no basis in data and therefore no claim to fair representation. But to cover up one mistake with another that has grave consequences for voters is unacceptable. This Special Session should not be used to distract attention from women's reservation with talk of increasing seats and delimitation. Unlike women's reservation, expansion and delimitation are linked to population counts. Any increase of seats and fresh delimitation should only be undertaken after the ongoing Census' results are published. What this Special Session can do is restore the focus on women's reservation. It should amend the 2023 Nari Shakti Vandan Adhiniyam to delete all references to

the Census and delimitation, since, as we have said above, it can be done on the current strength of the legislatures too, if parliamentarians agree on doing it before the 2029 general election. Secondly, any increase in the number of women's seats depends on overall increases: that is, it will be done automatically after any future seat expansions. Any proposal to replace the 2026 Census with the 2011 Census is thus infructuous. The next glaring gap in the 2023 Act is the failure to specify that the 33% reserved women's seats will be allocated to states in proportion to each state's existing seat share.



Maintaining a balance between equal elector weight and fair states' representation is essential to the federal nature of the Indian Union. The principle of ensuring that states that have invested in human development, especially women's welfare, education and financial independence are protected rather than penalized led to the freezes on Lok Sabha expansion in 1976 and 2001. The proposed Constitutional Amendment Bill omits any protection for the demographically and economically well-performing states; there is no clause that even freezes the current states' seat shares at the same proportion. That clause is missing in the Nari Shakti Vandan Adhiniyam too. It needs to be inserted, saying that the 33% allocation in the Lok Sabha will be

distributed to states as a one-third proportion of their current seats' allocation.

Similarly, though 8% of the 33% women's seats are reserved for SC/ST women, there is no provision to provide state funding for their election campaigns. Women from other vulnerable and marginalized groups might need funding too. This is another clause to be inserted in the existing 2023 Act.

Finally, the Special session should resolve to introduce a new Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026, for 33% reservation of women's seats in the Rajya Sabha, in the upcoming monsoon session. When Lok Sabha reservation was agreed in 2023, why is Rajya Sabha reservation lagging behind? These points and others have been made by a women's petition to MPs, organized by an ad-hoc group called the Women's Coalition for Women's Representation. The petition has been signed by over 500 people from over 65 civil society groups, from individuals to organizations spanning women's rights, LGBTQI demands, equal representation, municipal councils, panchayats and Mahila Mandals, and child rights. The concerns of these groups deserve to be heard, as do their proposed amendments. As do the concerns of Opposition parties. Government and ruling party spokespeople seek to present any

criticism of the proposed Bills as a failure to uphold women's rights. But the points made by these 65+ civil society groups are not merely opposition to the Bills, they are suggestions from women on ways in which women's reservation can be strengthened as well as implemented. They are also points that the Opposition parties can accept, indeed should accept. If the government allows proper discussion on and acceptance of them in this Special Session, then the much desired parliamentary unity that the Government talks of might be achievable. Without showing openness to Opposition and civil society views, the government sends the message of arbitrary high-handedness. The ball is in their court this time.

Sewers of death: Troubling gap between policy & practice

Prosecutions are rare and systemic reform even rarer

THE tragic death of two sanitation workers during sewer cleaning in Haryana's Nuh, with another battling for life, is a pointer to a system that continues to fail its most invisible workers. Despite a legal ban, hazardous manual cleaning of sewers persists, exposing a troubling gap between policy and practice. These deaths are rarely "accidents." They are the predictable outcome of sending workers into toxic, oxygen-deprived spaces without protective gear, training or supervision. The presence of lethal gases such as methane and hydrogen sulphide in sewers is well known. Yet, safety protocols are routinely ignored, often by contractors seeking to cut costs and by authorities that look the other way. In the past five years, at least 315 sanitation workers have died cleaning sewers and septic tanks across India, with Haryana being among the worst affected. The country outlawed manual scavenging under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, but enforcement



remains weak. Mechanised cleaning, mandated as the norm, is either unavailable or underutilised, particularly in smaller towns. When deaths occur, compensation may be announced, but accountability is diluted. Prosecutions are rare and systemic reform even rarer.

There is also an uncomfortable social dimension. Sanitation work continues to be performed largely by marginalised communities, perpetuating a cycle of vulnerability and neglect. The persistence of such practices raises fundamental questions about dignity, equality and the value placed on human life. Decisive action is needed. Strict criminal liability must be enforced against those responsible for violating safety norms. Urban local bodies must ensure universal mechanisation of sewer cleaning. Most importantly, the state must recognise that these are not faceless labourers but citizens entitled to safety and dignity. Until then, sewers will remain silent death traps and the promise of reform, an empty one.

The imperial design of US nationalism

Education serves as an innocuous tool in America's grand project of global dominance

AN American businessman asked a surprising question soon after we had taken adjoining economy seats on a transatlantic flight. It seemed as if the question had bothered him for a long time. In the privacy of an aeroplane, he felt safe enough to ask: "Can you tell me who this guy called Shakespeare was?" I was puzzled, but I smiled. We had introduced ourselves a few minutes ago. He was running an ancillary business for a big computer company. Over the years, I have faced many complex questions from my students, but the difficulty with this question lay elsewhere. If someone didn't know who Shakespeare was, how would you establish his importance? To say that the Bard was a renowned dramatist wouldn't necessarily make sense to a middle-aged businessman. He had completed his education and a considerable part of his professional life without worrying about his ignorance of Shakespeare. Yet, there must be a cognitive void that he was aware of. He wanted to fill that void that very night. When I narrated this story to a friend who teaches literature, she rightly wondered why I felt so uptight about Shakespeare. Perhaps it was a sign of my post-colonial education, I conceded. Decolonisation is the current buzz, and it is growing comfortably alongside an unrecognised counter-trend inspired by the super-speciality focus associated with American education. Cultivation of literary sensibility is now the precinct of 'liberal arts'—the term American universities have exported. Our private universities have adopted it with passion, while despite a much-publicised policy shift, public universities are doggedly carrying on with the old nomenclature of arts faculty departments and degrees. And at the same time, American-style hyper-vocationalism is growing in our private universities. America is geographically distant, but our mental geography imparts it an emotional, inspiring

proximity. Generations of educated youth have been motivated to study and settle there. Successive Indian governments may have entertained doubts about US designs in South Asia, but few would doubt that the public perception in India has treated America as a symbol of opportunity and aspiration. Until quite recently, America symbolised democratic concerns and sensibility. The sight of Indians being sent back handcuffed on military planes created a shock which was soon absorbed. Nowadays, America's denial of global concerns like climate change has been perceived as one of the many eccentricities of the Donald Trump administration. His social media posts have similarly caused amusement more than serious surprise, and certainly not revulsion. His recent announcement of the imminent death of a civilisation was no exception. Abusive words for the nation that America regards as an evil enemy seemed to cross a vague grey, rather than red, line in public discourse. Did the death of a civilisation contain a nuclear threat, many wondered.

America dropped two atomic bombs during World War II, but no US President has expressed regret or vowed future avoidance. Also, there has never been a consensus that American children should learn about Hiroshima with embarrassment. During Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's visit to the US in March, Trump did not hesitate to mention Japan's bombing of Pearl Harbour in 1941. Four years later, Japan had surrendered when the US dropped freshly manufactured bombs on Hiroshima and Nagasaki. Although history books make it a point to deny that these endgame attacks on the two Japanese cities were acts of retribution, any reference to Pearl Harbour usually invokes the nuclear conclusion of the war. Apparently,

Trump did not mind awakening in his Japanese visitor's mind the terrible memory of Hiroshima and Nagasaki. Throughout the ongoing war with Iran, he has maintained a persona of a powerful man who stays cool and jokes about inflicting a hellish experience on ordinary people.

Trump represents a country famous for many universities. They hold a fascination for our youth. I have lost many



of my bright and hard-working students to Trump's nation. He is the democratically chosen leader of his country. If you believe that education should nurture certain basic values like concern for life, his description of bombs and bomber planes as beautiful sounds alarming. When he turns funny in front of journalists, many of them can be heard laughing, suggesting that he is not alone in entertaining violent thoughts. His discourse does represent a wider change in America's public mind. Perhaps it is not a change, but merely an

evolution—and we are expected to ignore its meaning.

A few years ago, an opportunity to grasp the nature of American nationalism came my way quite unexpectedly. A senior friend from Jawaharlal Nehru University (JNU) told me that his son was not going to return home. Nothing extraordinary, I thought. He had finished his M.Phil in computer science. I knew that academic opportunities in computer science must be greater and more attractive in California than in Bengaluru. My JNU friend took out an envelope from his briefcase. It contained the report of his son's M.Phil thesis examiner in America. I looked at the report without much hope of understanding it because the discourse of computer science is Greek to me. But the last paragraph caught my eye. It pointed out with sharp clarity the link between research and nationalism. The examiner had recorded his view that this young man must be discouraged from going home because his work was necessary for maintaining America's leadership in the field.

The idea that knowledge is power is old and common, but its application to a gigantic political project is unique to America. Its project of global dominance has necessitated a model of nationalism which permits easy transfer of talent and feelings. The engineering of this transfer is essential to the imperial design of American nationalism. Education serves as an innocuous tool in this grand project. The popular metaphor that America is a melting pot does not reveal this political ambition.

It is not the first time in history that imperialism and nationalism have come together. Several European nations exemplified this blend in the 19th century when they were consolidating their economic hold across far-flung colonies.

Govt approves 2% dearness allowance hike for central govt employees, pensioners

New Delhi, (Agency)

The Union Cabinet has approved a 2% increase in Dearness Allowance (DA) for government employees and pensioners, according to sources following the Cabinet meeting. The Dearness Allowance is linked to inflation and is revised twice a year, usually in January and July. It is calculated using the Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW), which is released every month by the Labour Bureau under the Labour Ministry. This time, however, there was a delay in the announcement. The Confederation of Central Government Employees and Workers (CCGEW) expressed concern, noting that normally the hike is announced in late September and arrears are paid in early October. During the meeting, the Prime Minister sharply criticised the Opposition over its refusal to support the Women's Reservation Bill. He said the Opposition had made a serious mistake by not backing the bill and would have to bear the political cost in the future.

He asserted that the Opposition's stance reflects a negative mindset towards women and stressed that this message must reach every village across the country. The Prime Minister added that Opposition parties are now trying to justify their position after opposing the bill, and said they had effectively "defeated" the women of the country. The Cabinet also approved the creation of a Sovereign Maritime Fund with a corpus of Rs 13,000 crore. The fund aims to provide stable and affordable insurance coverage for Indian-flagged vessels, as well as ships operating to and from India. In addition, the Cabinet cleared the extension of the Prime Minister Gram Sadak Yojana (PMGSY) till 2028, with an additional allocation of Rs 3,000 crore.

US extends waiver allowing sale of Russian oil already at sea amid energy pressure

New Delhi, (Agency)

The Trump administration has issued a month-long sanctions waiver allowing the sale of Russian oil and petroleum products already at sea, extending an earlier relaxation of restrictions amid surging global energy prices. India has been among the major beneficiaries of these waivers. The license, issued by the United States Department of the Treasury, came two days after Treasury Secretary Scott Bessent said Washington would not renew waivers for Russian or Iranian oil. The order permits transactions involving oil and petroleum products loaded onto vessels as of Friday through 12:01 am (0401 GMT) on May 16. It replaces and supersedes General License No. 134A, which expired on April 11, with General License No. 134B. The US had earlier granted a series of temporary exemptions, including a one-month waiver beginning March 5 allowing India to purchase Russian oil, followed by similar permissions for other countries. These exemptions also ended on April 11. India has been among the major beneficiaries of the waivers.

The latest general licence does not authorise any transactions involving persons, entities or joint ventures in Iran, North Korea, Cuba or parts of Ukraine. The move follows heightened volatility in global energy markets after disruptions in the Strait of Hormuz, which intensified after Tehran's retaliation to the US-Israeli war against Iran. The developments pushed up oil prices and US gasoline costs, adding pressure on households ahead of key midterm elections. The waiver also comes amid concerns in Western capitals over continued Russian oil revenues funding its war in Ukraine, launched in 2022 and now the deadliest conflict in Europe since World War II.

SEC, Adanis seek extension, propose new briefing schedule in US case

New Delhi, (Agency)

The US Securities and Exchange Commission and Indian businessmen Gautam Adani and Sagar Adani have jointly requested a US court for more time to file key submissions in a civil securities case, proposing a revised schedule for motions and responses.

In a filing before the US District Court for the Eastern District of New York, the parties said they had conferred in line with the court's April 7 directive and agreed on a new timeline, which has been submitted for approval to Judge Nicholas G Garaufis. The SEC had sued Adani Group founder Gautam Adani and his nephew, Sagar, in November 2024, alleging they had misled investors by failing to disclose an alleged bribery scheme tied to Indian state officials, framing the case under US securities laws. Denying all allegations, the two, through their lawyers, on April 7, filed a pre-motion letter ahead of a planned April 30 motion, seeking dismissal of a fraud lawsuit, arguing the case represents an impermissible extraterritorial application of US law and fails for lack of personal jurisdiction. Under the proposed schedule, the defendant's (Adanis) motion to dismiss would be due by June 8, the SEC's amended complaint or opposition by August 7, and the defendants' reply by September 21. The parties also suggested May 20, May 22 or May 29 as potential dates for a pre-motion conference, subject to the court's availability. The request follows a pre-motion letter filed by the defendants on April 7, after which the court directed both sides to confer on next steps. In their anticipated motion to dismiss, Adanis are expected to argue that the court lacks jurisdiction because the claims concern conduct outside the United States, that the alleged statements are too general to be relied upon by investors, and that they were not involved in a \$750 million bond offering in 2021. The SEC filed the lawsuit in November 2024, alleging violations of US securities laws. An earlier briefing schedule approved in January set April 30 as the deadline for the motion to dismiss, June 29 for the SEC's response and August 13 for the defendants' reply.

Below-normal monsoon, West Asia conflict cloud India's agriculture outlook

New Delhi, (Agency)

A looming below-normal monsoon forecast and the ongoing West Asia conflict has cast a shadow over the future of the Indian agricultural sector as it threatens to disrupt production and rural economic growth. The India Meteorological Department (IMD) issued its first long-range forecast for the 2026 Southwest Monsoon, estimating rainfall at 92 per cent of the Long Period Average (LPA). This projection represents the lowest initial forecast in at least 25 years and indicates a sharp reversal from the above-normal rainfall recorded during 2024 and 2025. Bank of Baroda noted that the performance of the monsoon carries heavy weight for the broader economy. "Total rainfall has a close relation with both kharif and rabi output and hence will have an impact on overall growth in farm income and hence rural consumption," the Bank stated.

The geopolitical situation in West Asia further complicates the outlook for the current year. The conflict has caused disruptions in the supply of gas, which is a primary component in the production of essential farming inputs. "A good supply of water is a necessary condition for a good harvest although this year, due to the disruptions caused in supply of gas due to the war, other inputs that go into agriculture like availability and cost of fertilizers and pesticides will also have a bearing on the final outcome," the statement added. Given that irrigation coverage in India ranged from only 50 to 60 per cent over the last five years, rainfall remains vital for several crops, especially those grown in the interior regions. Beyond field crops, the monsoon determines reservoir levels for year-round water supplies and influences allied

agricultural activities. The Bank tracks these impacts across two distinct periods,



using the July-September and October-December quarters to cover kharif outcomes, while the January-June period accounts for rabi production. "This measurement also includes non-crop items such as horticulture, tobacco, and rubber," the Bank said. Historical data suggests a strong correlation between monsoon performance and agricultural

growth rates. According to the bank, the correlation coefficient for kharif production with actual monsoon performance is 0.64, while rabi stands at 0.59. This indicates that kharif crops tend to be more dependent on rainfall levels than the rabi season.

"Sub-normal monsoon i.e. less than 96% of LPA has been associated with lower growth rates in agriculture. In 2014-15 and 2015-16 when monsoon was less than 90% of normal, kharif production had declined. But in these years, rabi production was positive and significant," the bank said. The growth of value addition in agriculture is currently reckoned over a 12-year period starting from 2012-13. With the IMD's midpoint estimate for 2026 falling below the levels seen in previous decades, the sector remains under watch for its impact on overall GDP calculations and the stability of rural incomes.

India's auto sector faces risks if West Asia conflict prolongs: FADA

New Delhi, (Agency)

The President of the Federation of Automobile Dealers Associations (FADA), C.S. Vigneshwar, has raised concerns about the potential impact of prolonged conflict in West Asia on India's automotive sector.

Speaking on the sidelines of the Vyapar Delhi event, Vigneshwar said that ongoing geopolitical tensions could disrupt exports and affect the supply of key inputs such as oil and aluminium. While India's domestic auto market has shown strong resilience following a period of robust growth, extended instability could pose challenges for both production and global trade.

He explained that the sector is particularly vulnerable to fluctuations in oil supply, which affects fuel, lubricants, and overall vehicle operations. In addition, shortages of gas

and aluminium could hinder manufacturing. Although he expressed confidence in government efforts to mitigate these risks, he acknowledged that the industry may face difficulties in the coming months if the conflict continues. Vigneshwar also highlighted concerns about a potential decline in vehicle exports, even as domestic demand remains strong. He noted that the industry recorded approximately 13% growth across segments last year, providing a buffer against global uncertainties.

Despite possible disruptions, he remains optimistic about continued domestic production.

He further emphasized the importance of managing supply chain disruptions, especially given India's dependence on imported resources like lithium. Stressing the need for balance, he called

for accelerated development of domestic lithium reserves and battery manufacturing capabilities.

On the electric vehicle (EV) front, Vigneshwar pointed out steady growth in adoption rates. Electric two-wheelers have reached around 9% market share, while passenger vehicles stand at about 5-6%, and commercial vehicles at roughly 2%. He underscored the importance of building a strong ecosystem to support cleaner mobility solutions and prepare for future demand. The Vyapar Delhi event brought together dealers, OEMs, policymakers, and industry stakeholders, including the Chief Minister of Delhi, as well as representatives from insurance and finance sectors, to discuss challenges and shape future policy directions for the automotive industry.

On paper, compliant: How labour laws are quietly undermined

New Delhi, (Agency)

The labour uprising in Noida for low wages, wrong wages (actual payouts being less than salaries in the records) and poor working conditions, is a perfect case for arguing why we need a strict regulatory structure, even if that structure is derided as inspector raj.

What appears as compliance in official records often conceals deliberate strategies to deny workers their legal protections—revealing a deeper failure of enforcement. What is often presented as "smart management" is, in reality, a calculated evasion of the law. Across industries, employers—frequently aided by labour consultants acting as intermediaries—deploy methods that systematically deny workers their rightful protections. More troubling is the role of certain officials who choose to enable or overlook such practices.

In one instance, a factory inspector conducted a routine visit and reported full compliance. According to his findings, several workers were engaged by contractors outside the factory premises, in areas not covered under the Employees' State Insurance (ESI) Act.

He further stated that the employer neither supervised their work nor exercised control over them. On this basis, the employer was deemed free from liability for statutory contributions in respect of contract workers. The conclusion was convenient, and entirely misleading. This version went unchallenged until an accident altered the course of events.

A junior-level local office manager, known for his integrity, visited the factory to investigate the incident. His role was limited to accident enquiries, not regular inspections. However, his observations told a different story: on the day of his visit, he found at least ten workers employed within the factory premises without being brought under ESI coverage. His report led to a special inspection being assigned to me. The factory manufactured agricultural implements and bus bodies using electrically operated machinery. These operations were carried out within the premises through two so-called contractors—one handling framework and the other sheet metal work. The employer claimed that such work was occasional, limited to about ten days a month. The reality was otherwise.

Govt strengthens DGFT Norms Committees to speed up export authorisations, cut delays

New Delhi, (Agency)

The Ministry of Commerce and Industry has introduced a set of reforms to improve the functioning of Norms Committees under the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), aimed at faster disposal of Advance Authorisation applications and easing process for exporters.

In an official statement, the ministry stated that the move comes as part of the government's broader push to enhance ease of doing business and reduce delays in approvals under export-linked schemes. The Ministry noted that "DGFT administers the Advance Authorisation (AA) Scheme and the Duty-Free Import Authorisation (DFIA) Scheme under the Foreign Trade Policy. These schemes allow duty-free import of inputs that are physically incorporated in export products." At present, seven such committees operate across sectors, comprising technical experts and officials from various ministries. However, their functioning had been impacted by capacity constraints,

leading to a rise in pending applications. To address this, the government has introduced process and capacity-related reforms. These include

number of technical members has increased from 12 to 22, improving the committees' ability to handle a higher volume of cases.

A special disposal drive has also been launched to clear pending applications in a time-bound manner, with cases being taken up in chronological order to ensure transparency. According to the ministry, these measures have already begun to show results. Between January 2026 and April 7, 2026, a total of 38 committee meetings were held, during which 3,925 cases were reviewed and 1,770 cases disposed of.

The reforms are expected to reduce transaction costs, shorten approval timelines, and provide greater predictability for exporters, particularly small and medium enterprises.

The ministry will continue to refine the norms mechanism to support export growth and improve overall trade facilitation.



fixed scheduling of meetings on a fortnightly basis, prioritisation of long-pending cases, and time-bound finalisation of meeting minutes. Monitoring mechanisms for pendency and case ageing have also been strengthened. In addition, line ministries have been asked to nominate more technical experts to the committees. As part of this effort, the

5 tonnes gold, 8 tonnes silver stuck at customs since April 1 after DGFT lapse; import permissions restored for banks

Nearly 5 tonne of gold and 8 tonne of silver have remained stuck at Indian Customs since April 1 due to the lack of a formal government order authorising bullion imports

New Delhi, (Agency)

A bureaucratic lapse by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) led to tonnes of imported gold and silver being held up at Customs since April 1 - an error that could have resulted in prices of precious metals going up ahead of Akshaya Tritiya. The issue, however, was rectified on Friday after the government renewed the list of banks authorised to import precious metals for FY27. Banks had permission to import gold and silver only until March 31, 2026. In the absence of a fresh notification, they halted import orders from overseas suppliers, resulting



in a pile-up of consignments at ports. According to media reports and economist estimates, around 5 tonne of gold and 8 tonnes of silver have remained stuck at Indian customs since April 1 due to the lack of a formal government order authorising bullion imports. The government, however, has not provided an official estimate. "It is difficult to give a consolidated figure right away because

multiple cargoes are stuck across several ports," a government source said. Officials from DGFT and Customs, when contacted, sought to attribute the lapse to each other. As per a notification issued by the Ministry of Commerce, 15 banks have been authorised to import both gold and silver, while two banks have been allowed to import only gold. The approval is effective from April 1, 2026, and will

remain valid until March 31, 2029. The previous order, issued in April 2025, had expired on March 31, 2026.

The 15 banks permitted to import both metals include Axis Bank, Bank of India, Deutsche Bank, Federal Bank, HDFC Bank, Punjab National Bank, ICICI Bank, IndusInd Bank, Indian Overseas Bank and Kotak Mahindra Bank, among others. Union Bank of India and Sberbank have been allowed to import only gold.

Importers other than those operating in special economic zones (SEZs) or export-oriented units (EOUs) will now require specific government licences to import precious metals. The rule has come into effect immediately, with no transition period, even for shipments already in transit. With Akshaya Tritiya approaching and banks unable to import during the interim, concerns had mounted over a potential spike in domestic prices.

Madhavi Arora, chief economist at Emkay Global, said: "No fresh imports from banks and reduced inflows imply supply tightening, drawdowns from existing stocks and ETF redemptions. This could lead to higher domestic premiums, especially around Akshaya Tritiya."

Pune airport runway opens for flights after shutdown due to IAF jet's hard landing

Pune Airport and police sources indicated that the aircraft may have suffered an undercarriage failure upon touchdown, leading to the blockage of the runway. The runway of the airport has now been restored and declared operational.

New Delhi.(Agency)
The Pune international airport runway has reopened for normal flight operations after it was temporarily shut down following an incident involving an Indian Air Force (IAF) aircraft hard landing during a routine night sortie at Air Force Station Lohegaon. The incident occurred around 10:25 pm on Friday, with both aircrew safe and no damage to civil property.



The runway remained closed for about nine hours as repairs and safety checks were carried out. IAF personnel worked overnight to restore operations, making the runway functional by 8:00 am on Saturday. Departures resumed at 7:30 am and arrivals at 8:00 am, with air traffic normalising gradually. "Reportedly Two pilots who were on a night sortie. Due to

the incident, all inbound and outbound commercial air traffic were halted until runway clearance was completed. This took around 9 hours," Mos civil aviation Murlidhar Mohol said on Saturday.

Late Friday night, IAF said that the runway at Pune airport was temporarily unavailable following an incident involving one of its

aircraft, disrupting both inbound and outbound commercial flight operations. "Pune runway is temporarily unavailable due to an incident involving an IAF aircraft. The aircrew are safe and there is no damage to civil property. Efforts are underway to operationalise the runway and resume normal operations at the earliest," the IAF said.

The Indian Air Force in a post on X later confirmed that the runway at Pune Airport, which was temporarily unavailable due to an incident involving an Indian Air Force aircraft, has now been restored and declared operational. All necessary safety inspections and clearances have been completed. Operations are resuming in a phased manner.

Airport and police sources indicated that the aircraft may have suffered an undercarriage failure upon touchdown, leading to the blockage of the runway. However, detailed

technical specifics have not yet been officially disclosed.

Authorities at Pune International Airport said the incident took place at approximately 10:25 pm. Following the occurrence, air traffic was immediately suspended as a safety precaution.

The airport, which operates under a dual-use model integrating civilian flights with an active Air Force station at Lohegaon, saw a complete halt in commercial operations.

During this period, airlines were notified of the disruption, and flight schedules were impacted accordingly.

Union Minister of State for Civil Aviation Murlidhar Mohol also confirmed the situation, reiterating that passenger safety remained uncompromised.

He stated that authorities worked closely to ensure the runway was cleared at the earliest and normal operations resumed without delay.

Air India pilot deported from US over alleged marijuana possession

New Delhi.(Agency)
An Air India pilot, travelling as a passenger on a flight from the national capital to San Francisco, was allegedly found in possession of marijuana and was sent back by the US authorities this week, according to sources. The pilot has been derostered, one of the sources told PTI.

"One of our crew members travelling from Delhi to San Francisco on 14 April, for positioning to operate a subsequent flight, was found to be inadmissible as per local laws and has been sent back to India," an airline spokesperson said in a statement on Friday.



According to sources, the co-pilot was allegedly found in possession of marijuana. The pilot was "deadheading" to San Francisco. An internal probe has been initiated by Air India, sources added.

Generally, 'deadheading' refers to a flight crew travelling as a passenger to his or her base station or to another place for duty.

The airline said appropriate strict disciplinary action would be taken as per laid-down company policies. "Air India maintains zero-tolerance towards any violation of the law and upholds the highest standards of safety, compliance, and professional conduct," it said in the statement. Further details could not be ascertained.

All accused arrested in assault on Army Brigadier and son in Delhi's Vasant Enclave

New Delhi.(Agency)
Four more people have been arrested in connection with the assault on an Indian Army Brigadier and his son in southwest Delhi's Vasant Enclave area. A senior police officer said that all remaining absconding accused in the case have now been arrested.

The accused have been identified as Surjit Singh (36), Sunil Sharma (53), Ashish (32), all residents of Mehram Nagar, and Satender (35), a resident of Bhiwani in Haryana.

Earlier, two accused had been arrested, and they have been identified as Satender, alias Sonu (49), and Sanjay Sharma (56), residents of Mehram Nagar.

According to police, Surjit is known to the main accused, Satender, and all of them were sitting together in Mehram Nagar when Satender received a call regarding the altercation in Vasant Enclave. Thereafter, they all went to the spot in Surjit's Hyundai Aura.

After reaching there, a quarrel broke out, after which they returned to their homes. Later, upon learning that a case had been registered, they absconded but were eventually apprehended and arrested. The car has been recovered, and further examination is under process, police said.

According to another police officer, the accused are evasive and not responding to the questions properly. The incident seems to be a spontaneous one. The incident unfolded on the night of April 11 when, as per the complainants, the brigadier and his son were on a walk after their dinner.

The Brigadier's son said "After dinner, my father and I were going for a walk. On the main road near the society exit, two people were drinking in a car. My father told them that this is a residential area and they should not drink here. They responded that they were locals and would drink there only; we should mind our own business".

Meanwhile, his father asked him to call the police but he said that the PCR was delayed. It took about 15 to 20 minutes for the PCR to arrive. In the meantime, the accused persons were also making phone calls. He added, "They continued drinking and later some eight people came out of two cars and started beating us". While speaking to the media, the Brigadier's wife said that the accused used abusive language and passed inappropriate comments. She further alleged that when she approached the policeman again, he refused to help and said that he would not intervene.

9 Kerala teachers die in Tamil Nadu after bus veers off road, hits multiple vehicles

New Delhi.(Agency)
At least nine people in Tamil Nadu's Salem district died, and several were left injured after a State Transport Corporation bus had a head-on collision with multiple vehicles on the Salem-Coimbatore national highway. All those who lost their lives in the tragedy were teachers by profession, news agency ANI reported.

As per a statement shared by the District Collector's office, the bus, which was heading to Salem from Coimbatore, suddenly veered off the road after the driver lost control while manoeuvring the 13th hairpin bend. It crashed into a two-wheeler and an autorickshaw, which was carrying nearly 10 passengers, and subsequently plunged into the 9th hairpin bend. The bus was carrying 13 tourists from Kerala's Perinthalmanna. Out of these 13,

eight people (1 male and seven females) died immediately on the spot. The five injured, which included the driver, two male juveniles aged between 17 and 18



years, and two females, were immediately rescued and taken to the government hospital in Pollachi. One of the injured later succumbed to their injuries.

The state authorities in Tamil Nadu reacted swiftly to the incident. Upon learning about the accident, two

senior police officers rushed to the spot and supervised the rescue and relief operations. Fire and Rescue Services personnel were also deployed to ensure a prompt evacuation of the injured.

PM, KERALA CM CONDOLE DEATHS

Prime Minister Narendra Modi expressed his grief over the loss of lives. "Distressed to hear about the mishap in Coimbatore, Tamil Nadu. I extend my heartfelt condolences to those who have lost their loved ones in the mishap. Prayers for the speedy recovery of those injured," the Prime Minister's office shared on X. Kerala Chief Minister, Pinarayi Vijayan, also expressed his condolences over the death of the Kerala citizens.

As per a report by PTI, Vijayan also gave instructions to the authorities to ensure the best possible treatment for all the injured people.

'Did Not Get Any Internal Complaint, Nida Khan Not HR Head': TCS Amid Probe

New Delhi.(Agency)
Amid the ongoing police probe into allegations of religious conversion and sexual misconduct at its Nashik unit, IT giant Tata Consultancy Services (TCS) on Friday said that it had not received any complaints through its internal channels on the matter.

"A preliminary review of the systems and records pertaining to the Nashik unit indicates that we have not received any complaints of the nature that are being alleged on either our ethics or POSH (prevention of sexual harassment) channels," the tech giant said.

The company also announced an oversight panel and engagement of external entities in its internal probe. Finance industry veteran Keki Mistry, an independent director on the company board, will be chairing the oversight committee, as per the statement. Police have arrested seven employees, including six men and a woman HR head.



Another employee, Nida Khan, is on the run. **TCS Nashik Case: What Are The Allegations**

The incident came to light after a woman accused a colleague, Danish Sheikh, of establishing a physical relationship with her after falsely promising marriage in 2022 - when he was already married to another woman.

According to a police report, Nida Khan is the sister of Danish Sheikh. She allegedly made derogatory remarks about the complainant's faith and attempted to pressure her to change her religion, the report said. It is further alleged that Khan and another individual, Tausif Akhtar, concealed the fact from the complainant that Danish Sheikh was already married to another woman.

As the police started investigating the matter, seven more women came forward, claiming that their senior colleagues mentally and sexually harassed them, and the human resources department ignored.

Sabarimala case: Supreme Court says religious practices open to legal scrutiny

In September 2018, a five-judge Constitution bench, by a 4:1 majority verdict, lifted the ban that prevented women between the ages of 10 and 50 from entering the Sabarimala Ayyappa temple and held that the centuries-old Hindu religious practice was illegal and unconstitutional.

New Delhi.(Agency)
The Supreme Court on Friday said judges must rise above personal religious beliefs and be guided by freedom of conscience and the broader constitutional framework while deciding matters of faith, adding that religious practices are open to legal scrutiny.

The nine-member bench made these observations while hearing the Sabarimala temple entry case. The apex court is reviewing its 2018 verdict that had lifted the prohibition on women between the ages of 10 and 50 years from entering the temple.

Senior advocate Rajeev Dhavan, appearing for an intervenor, said the case goes beyond Hindu practices or the Sabarimala issue and deals with the constitutional framework governing all religions and matters of conscience.



The concern is to lay down the law for everybody, every belief and every matter of conscience," Dhavan said, adding that the court's endeavour must be to harmonise when there are divisions in society. He argued that an individual can question a religion, but it must be in a respectful manner.

At this juncture, Justice Nagarathna asked Dhavan, "Are you saying conscience is

something larger than religion? Should conscience take the colour of religion?" Justice Amanullah asked him: "Are you suggesting that judges should not equate religion with conscience, and must rise above personal beliefs to balance them with the Constitution and see the bigger picture?" Dhavan replied that it is the apex court's discretion to interpret conscience in a manner in which they deem it appropriate.

WHAT SABARIMALA PETITIONERS ARGUED TODAY

Senior advocate V Giri, appearing for Sabarimala Acharya Samrakshana Samiti, submitted that there is collectively a wisdom that has been followed for years and years in exclusion of women aged between 10-50 not being allowed in Sabarimala temple.

Giri submitted that every temple has its own distinct characteristic and the maintenance of those characteristics is part of the worship.

Delhi plans flyovers, underpasses on key stretches to decongest North and South Delhi roads

Public Works Department Delhi to build integrated corridor project covering Mehrauli-Mahipalpur, Kanti Nagar, Bawana and Kanjhawala stretches to ease traffic congestion across about 34 km.

New Delhi.(Agency)

Aiming to decongest four key road stretches in South and North Delhi, the government has planned to construct flyovers and underpasses. The Public Works Department (PWD) will construct these flyovers and underpasses under the integrated road corridor project.

The project included construction of flyovers at Mehrauli-Mahipalpur Road - including Aruna Asaf Ali Road - at Kanti Nagar bridge intersection, and a flyover in Bawana and near Kanjhawala Chowk, totalling around 34 kilometres of road stretch decongestion.

"Traffic at these intersections experiences heavy traffic flow, resulting in frequent traffic jams. Construction of an underpass or flyover appears to be a feasible traffic movement. A tender has been floated in this regard," sources said.

The Mehrauli-Mahipalpur road connecting to Aruna Asaf Ali Road near the JNU campus is approximately a 9 km long stretch. To ease traffic congestion on this stretch, the department plans to construct a flyover, an underpass and a U-turn under the flyover.

"Between Kanti Nagar bridge and Telco T-point, which is connected to Mahipalpur Road, approximately a 6 km stretch also faces traffic congestion where the PWD plans to construct a flyover," sources added.

The 9-km stretch in North Delhi's Bawana Road is also said to be decongested after the flyover.

The PWD plans to conduct a feasibility study for the construction of a flyover from Kanjhawala Chowk to Mangolpuri on Outer Ring Road in North Delhi at a cost of ₹3.44 crore. The study will be conducted for a period of four to five months to decongest a stretch of approximately 10 km in length.

NEWS BOX

Mythos "Serious Threat" To Banks, New Models May Be "Distressing": Barclays CEO

World. (Agency)

Anthropic's frontier AI model Mythos is a serious threat to the global banking system, and it is likely to be followed by similar, even more powerful cyberthreats, Barclays Chief Executive CS Venkatakrishnan said on Friday. The vast capabilities of Mythos to code at a high level have given it a potentially unprecedented ability to identify cybersecurity vulnerabilities and devise ways to exploit them, raising fears it could be exploited to destabilise banks. This has forced regulators and supervisors into a scramble, and selected organisations are now reviewing the model to gauge the actual cybersecurity risk. Mythos has raised alarm bells among regulators, who see it as a significant challenge to the banking sector and its legacy technology systems. "On Mythos, look, it's a serious issue," he told a meeting of the G30 consultancy group on the sidelines of the IMF's spring meeting.

"But here's the thing: there will be a Mythos 2 and a Mythos 3, and they'll come up with probably distressing frequency," he said. Such technological leaps will accelerate an arms race that forces lenders to innovate, and may be especially challenging for older and larger institutions potentially running legacy systems, Venkatakrishnan said. We have to understand its capabilities and we have to understand how to safeguard against it."

Boeing Sees Boost In Military Contracts Amid War In Middle East

World. (Agency)

The Middle East war has so far boosted Boeing's defense business and hasn't impacted deliveries to airline customers confronting high jet fuel prices, the company's CEO said Friday. Kelly Ortberg cited a recent agreement with the US military to triple production of PAC-3 seekers, which identify and strike hostile aircraft and weapons, as an example of increased demand due to the war.

"When you see a major step up in (operations) tempo for our defense products, that opens up the opportunity for more service, spare parts, maintenance actions," Ortberg said during the company's annual meeting. He described the jump in jet fuel prices as a priority for Boeing's airline customers. "At this point, I'd have to say we have not seen any impact on airplane deliveries from any of our customers," Ortberg said. "We'll have to watch this and continue to monitor it." Worries over scarce jet fuel became more acute earlier this week, with the International Energy Agency head saying Europe was about six weeks away from a shortage.

But Boeing's annual meeting started shortly after Iran announced it was reopening the Strait of Hormuz shipping channel, leading to a sharp pullback in oil prices. If crude oil deliveries are restored as expected, supply of jet fuel will improve. Boeing shares rose about four percent in mid-morning trading.

Meta To Lay Off Around 8,000 Employees By Next Month: Report

World. (Agency)

Meta intends to conduct a first wave of sweeping layoffs planned for this year on May 20, with more coming later, three sources familiar with the plans told Reuters. The Facebook and Instagram owner will lay off about 10% of its global workforce, or close to 8,000 employees, in that initial round, one of the sources said. The company is planning further layoffs in the second half of the year, the three sources said, although details of those cuts, including date and size, were not yet settled. Executives may adjust their plans as they observe developments in artificial intelligence capabilities, the sources added. Reuters reported last month that the company was planning to lay off 20% or more of its global workforce.

Meta declined to comment on the timing or scope of planned cuts. CEO Mark Zuckerberg is pumping hundreds of billions of dollars into AI as he seeks to dramatically reshape his company's inner workings around the technology, reflecting a broader pattern among major US companies this year, particularly in the tech sector. Amazon.com similarly has trimmed 30,000 corporate employees in recent months, representing nearly 10% of its white-collar workers, while in February the fintech company Block chopped nearly half of its staff.

In both of those cases, executives tied the cuts to efficiency gains from artificial intelligence.

Layoffs.fyi, a website tracking tech job cuts around the world, reported that 73,212 employees have lost their jobs so far this year. For all of 2024, the figure was 153,000. Meta's layoffs this year will be the social media giant's most significant since a restructuring in late 2022 and early 2023 that it dubbed the "year of efficiency," when it eliminated about 21,000 jobs. At that time, Meta's stock was in freefall and the company was struggling to correct for COVID-era growth assumptions that ultimately proved unsustainable. The company is in a more comfortable financial position this time, but executives envision a future of fewer management layers and greater efficiency brought about by AI-assisted workers.

Meta's shares are up 3.68% since the start of the year, although they are down from a record high achieved last summer. Last year, it generated more than \$200 billion of revenue and achieved a \$60 billion profit despite outsized spending on artificial intelligence. Menlo Park, California-based Meta employed nearly 79,000 people as of December 31, according to its latest filing. In recent weeks, Meta has reorganized teams in its Reality Labs division and transferred engineers from throughout the company into a new "Applied AI" organization tasked with accelerating the development of AI agents that can write code and carry out complex tasks autonomously.

"US Will Start Dropping Bombs Again If No Deal Reached": Trump Warns Iran

Direct talks between the US and Iran last weekend were inconclusive, as the two nations could not agree about Iran's nuclear program and other points.

PARIS. (Agency)

Iran said it fully reopened the Strait of Hormuz to commercial vessels, but questions lingered Saturday about how much freedom ships actually had to transit the waterway as Tehran maintained its grip on the who got through and threatened to close it again if the US kept in place its blockade of Iranian ships and ports. Iran's Friday announcement about the opening of the crucial body of water, through which

20% of the world's oil is shipped, came as a 10-day truce between Israel and the Iranian-backed Hezbollah militant group in Lebanon appeared to hold.

US President Donald Trump, meanwhile, said the American blockade "will remain in full force" until Tehran reaches a deal with the US, including on its nuclear programme. Asked by a reporter Friday night what he will do if there's no deal when the ceasefire expires next week, Trump said, "I don't know. ... But maybe I won't extend it, so you'll have a blockade and unfortunately we'll have to start dropping bombs again." But he also told reporters accompanying him aboard Air Force One to Washington that a deal is "going to happen," and flatly rejected the idea of restrictions or tolls by Iran on the Strait of Hormuz. Trump had earlier celebrated the Iranian announcement, posting on social media that the strait was "fully open and ready for full passage." But

minutes later, he issued another post saying the US Navy's blockade would continue "UNTIL SUCH TIME AS OUR TRANSACTION WITH IRAN IS 100%

COMPLETE."

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi posted on X that ships would use routes designated by the Islamic Republic in coordination with Iranian authorities, suggesting Iran planned to retain some

level of control over the channel. It was not clear if vessels would have to pay tolls.

Iranian officials said the blockade was a violation of last week's ceasefire agreement between Iran and the US. The strait "will not remain open" if the blockade continues, Iran's parliamentary speaker, Mohammad Bagher Qalibaf, posted on X early Saturday.

A data firm, Kpler, said movement through the strait remained confined to corridors requiring Iran's approval. Trump imposed the blockade as part of his effort to force Iran to open the strait and accept a Pakistan-brokered ceasefire to end almost seven weeks of war that has raged between Israel, the US and Iran. The president's decision to continue the blockade despite Iran's announcement appeared aimed at sustaining pressure on Tehran as the fate of the two-week ceasefire reached last week remained uncertain.



"We Came In Fast And Hot": Artemis Astronauts On Re-Entry At 48,021 Kmph

World. (Agency)

The astronauts who flew around the moon and back in NASA's landmark Artemis II mission said their re-entry into Earth's atmosphere was smooth, but the mission's commander described some charring on the Orion capsule's critical heat shield.

The four Artemis II astronauts splashed down in the Pacific Ocean last Friday, capping a nearly 10-day test flight in which they reached the farthest distance in space any humans have gone before as their gumdrop-shaped Orion capsule sailed around the moon's far side. Speeding back into Earth's atmosphere at roughly 32 times the speed of sound, the finale of the high-stakes mission was a crucial test of the Lockheed Martin-built Orion capsule before NASA plans to use it again for another pre-lunar landing

flight in Earth's orbit next year. "We came in fast, and we came in hot," Artemis II mission commander Reid



Wiseman told reporters in the crew's first press conference since returning to Earth. In the months following the flight, NASA engineers will comb through hoards of data illustrating how well the Orion vehicle performed. They are likely to pay close attention to the capsule's heat shield, a critical

barrier that protects the crew from temperatures of up to 5,000 degrees Fahrenheit (2,760 degrees Celsius) during the descent from space.

In the 2022 Artemis I uncrewed mission, Orion's heat shield sustained far more damage than NASA had expected, showing small cracks and some layers charred off by its re-entry, leading to an intense two-year investigation. NASA did not upgrade the heat shield, but it changed the angle and trajectory in which the Artemis II crew entered Earth's atmosphere to reduce heat. Wiseman said he and mission pilot Victor Glover "maybe saw two moments of a touch of char loss" during re-entry. When they examined the capsule on the naval ship that recovered them from the ocean,

Indian among second group of migrants deported from US and taken in by Costa Rica

SAN JOSE. (Agency)

Costa Rica on Friday received a second group of migrants deported from the United States as part of an agreement to help the Trump administration's latest policy of deporting immigrants to "third countries." Under a bilateral agreement signed in March by Costa Rican President Rodrigo Chaves and U.S. Special Envoy Kristi Noem, Costa Rica has agreed to accept up to 25 third-country nationals expelled from the U.S. each week. The first group of 25 deportees, which arrived at San Jose's Juan Santamaria International Airport on Saturday, was assisted by Costa Rican migration police in coordination with the International Organization for Migration (IOM). A second group of third country deportees from the United States arrived in Costa Rica on Friday. The group of 30 deportees includes eight Costa Ricans, eight Brazilians, three Romanians, two Chinese nationals, three from Uzbekistan, two from Azerbaijan, one

from Ireland, one from India, one from Vietnam, and one from Belarus. Like the group that arrived Saturday, these



people will be offered the opportunity to participate in the Assisted Voluntary Return (AVR) program administered by the International Organization for Migration (IOM) to return to their countries of origin, or to apply for legal residency in Costa Rica under humanitarian categories through the standard process. The Central American nation is one of a growing number of countries across Africa and

the Americas that have signed contentious, often secretive agreements with the U.S. to accept deportees from other countries as U.S. President Donald Trump pressures governments to help him advance his agenda. In many cases, migrants who previously hoped to seek asylum in the U.S. are left in a legal "black hole" in foreign countries where they don't speak the language. Countries who have agreed to receive third-party migrants include South Sudan, Honduras, Rwanda, Guyana and several Caribbean islands like Dominica and St. Kitts and Nevis. The first group sent to Costa Rica included migrants from Albania, Kenya, Morocco, China, India and Cameroon, in addition to eight people from Guatemala and four Honduran nationals. The deportees were first taken to a hotel to receive assistance. During the first seven days in Costa Rica, they have the option of enrolling in a voluntary return program.

New German Search Engine Helps People Check Nazi Links In Family

YANGON. (Agency)

A new online tool from Germany is helping people learn more about their family history in a simple and direct way. The search engine allows users to check whether their ancestors were members of the Nazi Party, bringing hidden pasts into the open, reported BBC. The platform lets people search through millions of Nazi Party membership cards, known as the "NSDAP-Mitgliederkartei". It has already helped many users uncover surprising details about their families. One such user is Christian Rainer from Austria, who said he found his grandfather's name within seconds. He said that he found out that his grandfather became a member of the Nazi Party around April 21, 1938, just a few days after the Anschluss, when Adolf Hitler annexed Austria to Germany, reported BBC. Rainer further said that his grandfather applied to become a member of the NSDAP (Nazi) Party just five days after it became legal in Austria. He added that he had always known his grandfather was close to the Nazis, but he was surprised that it only took him five days to join them. Rainer never met his grandfather, who died shortly before he was born in 1961. He said the search engine was important not only for what it revealed about his grandfather, but also because it helped clear other members of his family.

He said he was happy he did not find anyone else from his family, especially not his father, and added that he had never suspected him of being a Nazi.

About The Search Engine According to BBC, the search tool was created by the German newspaper Die Zeit in cooperation with archives in Germany and the United States. According to the organisation, the response has been overwhelming.

Judith Busch, spokesperson for Die Zeit, said that the tool has been accessed millions of times and shared thousands of times since its launch at the beginning of April. Users have also shared emotional reactions. One user wrote that they had already found two close relatives, which destroys the myth that no one in their family was involved, and added that having their perspective changed at the age of 71 is a bitter shock.

Historical records show that around 10.2 million Germans became members of the Nazi Party between 1925 and 1945. The membership cards, originally stored at Nazi headquarters in Munich, were almost destroyed during the final days of World War Two. However, they were saved by Hanns Huber, a paper mill director, who later handed them over to the Americans. These records later played an important role in the de-Nazification process in post-war Germany. For decades, they were kept at the Berlin Document Center before being transferred in 1994 to the German Federal Archives, with copies sent to the US National Archives in Washington DC.

French Widow, 85, Returns Home After Being Detained In US Amid Family Fight

The woman entered US to begin a new life with a retired US soldier she had met decades ago. But after her husband's death, Ross' stepson intervened to have her taken into immigration custody amid a dispute over estate

CAIRO. (Agency)

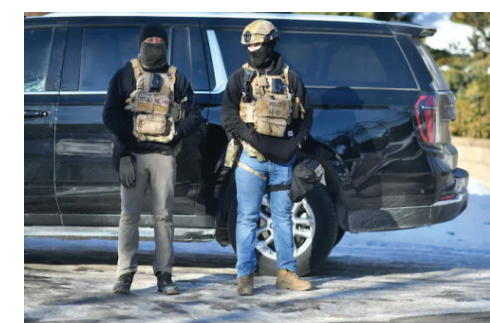
The 85-year-old widow of an American military veteran held in federal immigration detention returned home to France on Friday, according to the French government and her family.

Marie-Therese Ross entered the US last June to begin a new life with a retired US soldier she had met decades ago when he was stationed in France, court records show. But after her husband's death, Ross' stepson - a US federal employee - allegedly intervened to have her taken into immigration custody earlier this month amid a dispute over the estate, an Alabama judge found. "She returned to France this morning. This is a satisfaction for us," French Foreign Minister Jean-Noel Barrot told reporters during a visit to the southern city of Montpellier on Friday. Barrot said US Immigration and Customs Enforcement methods are "not in line" with French standards and are "not acceptable to us." Federal immigration agents detained Ross in

Alabama on April 1 after she overstayed her 90-day visa, according to the US Department of Homeland Security. She was then held at a detention facility in Louisiana as French officials expressed concern about her well-being. Ross' son, Herve Goix, told The Associated Press that she had been in the process of applying for a green card when she was taken into custody. She's very tired, she's not very good, but it's difficult for her," Goix said. "We are very, very happy, but we are tired." Ross was not given the medication she needed while being held in the Louisiana detention facility, according to her attorney Kim Willingham. "She does not feel she or other inmates are being treated well within the facility," Willingham told the AP. "She did everything she was supposed to do with regard to obtaining her green card."

Ross gave up her pension and moved to Alabama last year to marry William B Ross, a retired US soldier she had met

when he was stationed in France in the 1960s, Calhoun County court records



show. But after William B Ross died in January, his two sons became embroiled in a dispute with their stepmother over the modest estate, including the home in Anniston, Alabama, where she resided.

The sons rerouted mail from the residence, leading their stepmother to miss an immigration-related appointment,

Calhoun County Probate Judge Shirley A. Millwood noted in a court order earlier this month. Millwood accused one son of using his position as a federal employee to prompt the detention of his stepmother days before a hearing over the estate. Marie-Therese Ross was taken into custody in her nightgown and unable to bring her phone, passport and other identification with her, records show.

The stepson denied involvement in his stepmother's arrest in court, but Millwood said evidence indicated he knew in advance of the arrest and received a text message confirming it shortly afterward. His brother then arrived at the home to change the locks two hours after federal immigration agents removed their stepmother. In an April 10 ruling, Millwood ordered the stepsons to allow Ross to retrieve her clothes, phone, documents and other possessions from her late husband's home.

NEWS BOX

Brendon McCullum to rejoin KKR? Pietersen makes wild prediction for next IPL season

Ahmedabad. (Agency)

The Kolkata Knight Riders (KKR) find themselves in an unprecedented crisis during the 2026 IPL season. Following another demoralizing five-wicket defeat to the Gujarat Titans on Friday, April 17, former England captain Kevin Pietersen took to social media to drop a bombshell prediction regarding the franchise's future leadership.

Pietersen's social media post has sparked intense debate among the cricketing fraternity, especially as the three-time champions continue to search for their first victory of the campaign. "Baz McCullum will be the coach of KKR next season. Bookmark this tweet," Pietersen posted on X. The statement has quickly gone viral as the KKR faithful search for answers following a historically poor start to the year. The timing of the comment is particularly poignant given KKR's inability to translate their talent into points on the board.

A Season of Historic Struggles



The three-time champions are currently enduring possibly their worst-ever opening to an IPL campaign. After six matches, KKR remains the only winless team in the tournament. They currently languish at the bottom of the table with a solitary point, which was earned only through a rain-abandoned fixture against the Punjab Kings. Even in their most recent clash against the Gujarat Titans, a fighting 79 from Cameron Green was not enough to stop Shubman Gill's side from chasing down 181 with two balls to spare. The current leadership group, led by head coach Abhishek Nayar and captain Ajinkya Rahane, has faced increasing scrutiny. Despite a high-profile coaching staff that includes names like Dwayne Bravo and Shane Watson, the team has struggled to find a consistent winning formula. Critics have noted the absence of a strong mentor figure in the dugout, particularly following the departure of Gautam Gambhir, who was a key part of the franchise's third title win in 2024. The McCullum Legacy.

Congratulations after a loss? The bizarre exchange that left Ajinkya Rahane moved

NEW DELHI. (Agency)

In the sterile, high-pressure environment of a post-match press conference, these six words felt like a lifeline. For Ajinkya Rahane, the despondent skipper of a Kolkata Knight Riders side currently sinking without a trace, the comment was as unexpected as it was welcome. GT vs KKR: HIGHLIGHTS | SCORECARD

"Thank you so much, thank you," Rahane replied, a flicker of genuine emotion breaking through his usually stoic exterior. Someone really appreciated my hard work. "It was a rare moment of relief amid the deafening noise of a campaign gone haywire. For a veteran who has spent the last month dodging questions about his strike rate and KKR's tactical blunders, the simple acknowledgement of his effort seemed to weigh more than the two points lost on the field. But the warmth of that



exchange couldn't mask the chill of the league table. KKR's visit to Gujarat resulted in their fifth defeat in six matches, a staggering slump that leaves them as the only winless outfit in IPL 2026. At the Narendra Modi Stadium, the narrative was tragically familiar. Despite a flurry of early wickets, the Knight Riders' bowling unit failed to tighten the noose, allowing the Titans to gallop home with overs to spare.

Rahane, dismissed cheaply early in the innings, looked a man carrying the world on his shoulders during the chase. When asked what he could possibly take away from such a sustained period of failure, he remained philosophical. "Every day is a learning thing," Rahane noted. "Whether we win or lose, whenever we go onto the field, be it a match or practice session, it is all about learning. It's about winning the key moments as a batting unit or bowling unit. T20 is all about winning at key moments.

Andreeva sinks Swiatek to meet top seed Rybakina in Stuttgart semis

Swiatek has won four of her six Grand Slams on the French Open clay and was considered among the favourites but struggled against the energetic Russian.

STUTTGART. (Agency)

Top seed Elena Rybakina saved two match points against unseeded Canadian Leylah Fernandez to advance to the semi-finals of the WTA Stuttgart tournament on Friday where she will meet Russian teenager Mirra Andreeva. Rybakina, the 2024 Stuttgart winner, needed three hours to get past Fernandez 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (8/6), saving two match points in the final-set tiebreak.

Earlier Andreeva rallied past two-time Stuttgart champion Iga Swiatek 3-6, 6-4, 6-3. "Especially in the beginning there was a lot of frustration. I was just going downhill. The

serve was not going," Rybakina said.

"Somehow I found the fight in me and a couple of points were important in the second set. And somehow I started finding this momentum." Swiatek has won four of her six Grand Slams on the French Open clay and was considered among the favourites but struggled against the energetic Russian.

The Pole capitalised on some clumsy baseline errors from her opponent to win the opening set but Andreeva converted a crucial break point to take the second set. Swiatek ran out to a two-game lead in the deciding set but Andreeva broke back twice to take the initiative, and the match. The 18-year-old rising star also eliminated defending champion Jelena Ostapenko in the first round of the tournament. "She's won so many tournaments I can't even count how many Slams she's won... she's a past winner of this



tournament as well," Andreeva said. "I was telling myself: 'No matter what's happening, I have to keep fighting and keep believing. I can win from any score.'"

Gauff crashes

Earlier Karolina Muchova broke through for a first win over Coco Gauff, eliminating the reigning French Open champion 6-3, 5-7, 6-3 to reach the Stuttgart semi-finals for the first time. The 12th-ranked Muchova will

face Elina Svitolina for a place in the final. Muchova had never beaten world number three Gauff in six matches, including a loss in the fourth round of this year's Australian Open, but prevailed for the first time.

After ensuring Gauff exited the tournament in the quarter-finals for the third straight year, Muchova said she tried not to let the daunting record impact her preparation.

"It was a great fight. I'm just happy that I finally, finally beat her," Muchova said.

"This was actually our first match on a clay court. On clay we were 0-0 in the matches -- I tried to keep it positive." Fourth seed Svitolina moved past Czech Linda Noskova 7-6 (7/2), 7-5 to book her semi-final spot. The in-form Ukrainian has now reached five semi-finals this season. Svitolina told reporters she had rediscovered her fighting spirit after a difficult 2025. "I had a really difficult end of last year, struggling a bit mentally," Svitolina said.

IPL 2026: Mahi Mania in Hyderabad, CSK eye first away win against rejuvenated SRH

Bengaluru. (Agency)

The Rajiv Gandhi International Stadium in Uppal is no stranger to high scores and high-octane drama, but Saturday evening promises to be a cracker, with more at stake than just two points. It is the quintessential Southern Derby, a collision of two franchises moving in opposite directions yet meeting at a fascinating crossroads. For the Chennai Super Kings, it is a quest to prove they can conquer the road; for the SunRisers Hyderabad, it is about proving their recent demolition of the league leaders was no flash in the pan. The air in Hyderabad usually carries the scent of Irani chai and biryani, but this week it is thick with the musk of 'Mahi Mania'. For the first time in the 2026 season, the familiar No. 7 has boarded the team bus for an away fixture. After a frustrating five-match hiatus due to a stubborn groin strain, one that saw him anchored in Chennai while the team travelled to Guwahati and Bengaluru, MS Dhoni has landed in the Nizam's city. The reception for 'Thala' at the airport on Thursday was a testament to a legacy that refuses to dim. The roars were deafening, and a massive cut-out near the stadium stands as a sentinel to the fans' devotion. However, the romanticism of his arrival is tempered by cold, professional caution. While the excitement is palpable, word from the CSK camp suggests they are not

MI should pay Deepak Chahar and Shardul, ask them to go home: Ex-India captain

R Ashwin warns that T20 World Cup fatigue is hitting Mumbai Indians' stars after a 4th IPL 2026 loss. Hardik Pandya hints at "tough calls" as MI struggles to find answers with the ball.

Mumbai. (Agency)

Former India captain Kris Srikkanth did not hold back in his criticism of Shardul Thakur and Deepak Chahar, stating that the two bowlers do not deserve to be part of the Mumbai Indians in IPL 2026. In a forthright comment, Srikkanth urged the Mumbai Indians management to pay the two cricketers and ask them to stay away from the squad for the remainder of the season. Srikkanth's sharp assessment came after Mumbai Indians lost to Punjab Kings at Wankhede Stadium in Mumbai on Thursday, April 16. Mumbai Indians posted 195 in 20 overs, a below-par total on a good batting pitch. On a dewy evening, Punjab Kings made light work of the chase, reaching the target in just 16.2 overs.

Despite knowing Punjab Kings opener Prabhsimran Singh and Priyash Arya were in fine form, Mumbai did not open the bowling with Jasprit Bumrah. Instead,

Deepak Chahar, who opened the bowling, conceded 21 runs, setting a poor tone for their defence. Prabhsimran attacked the



bowling, scoring 80 off 39 balls. He was joined by captain Shreyas Iyer, who was in complete control with his 35-ball 66. While Jasprit Bumrah, under pressure, went wicketless and conceded 41 runs in four overs, Shardul and Deepak gave away 87 runs between them in just 5.3 overs. The two

were hit to all parts of the ground, and captain Hardik Pandya had no choice but to not utilise their full quota of four overs.

"I don't know how MI are playing Deepak Chahar in the XI. I don't know why they retained him. First over, he gave away 21 runs. In the previous match, it was 22 runs. 2.3 overs, 45 runs," Srikkanth said on his YouTube show. Our sir, Shardul Thakur. 3 overs, 42 runs. Combined, they bowled 5.3 overs and 87 runs. "How can you win a match if two of your important bowlers are giving away 87 runs in 5.3 overs? How can you play both of them in the XI? I asked that question in the pre-match show? Are you saying they don't have any good bowling options?" Send them home. Pay them their money and request them not to return this season. Tell them if they are needed, they will be called. Yes, you can do this. It's not wrong," he stated.

When Shreyas Iyer's blunder vs MI made Jonty Rhodes feel like grandfather of fielding

NEW DELHI. (Agency)

The Wankhede Stadium, a venue renowned for its legendary moments, witnessed another historic feat during the high-stakes match between the Mumbai Indians and the Punjab Kings. Amidst the electrifying atmosphere, Shreyas Iyer's extraordinary athletic display became the talk of the cricketing world, drawing praise from none other than Jonty Rhodes, the icon who transformed fielding into an art form.

Rhodes, who once set the benchmark for fielding excellence, was so impressed by Iyer's performance that he took to social media to express his admiration. In a post on X that rapidly gained traction, the South African legend acknowledged the unprecedented level of athleticism in modern cricket, a standard he never imagined during his playing days. Watching Shreyas Iyer perform that acrobatic fielding to assist in taking the 'team catch' made me appreciate how fielding has evolved since

my retirement," Rhodes remarked. He humorously reflected on his own legacy, noting that while he was once considered the "father of fielding," today's athletes make him feel like the "grandfather of



fielding." The moment of brilliance unfolded with the dismissal of Mumbai Indians' star Hardik Pandya. Facing a delivery that seemed destined for a six, Pandya connected with power and precision. However, Iyer, patrolling the boundary, had other plans. With impeccable

timing and awareness, he launched himself into the air, reaching back to intercept the ball even as his body was poised to land beyond the boundary. In a stunning mid-air maneuver, he managed to flick the ball back into play, allowing a teammate to complete the catch.

This gravity-defying act left the cricketing fraternity in awe. The dugout cameras captured the astonishment of Rohit Sharma and Suryakumar Yadav, both known for their own on-field heroics, as they witnessed Iyer's "hang-time" with wide eyes and open mouths. The Punjab Kings, currently in blistering form, have made this elite level of fielding a signature of their IPL 2026 campaign. As the only unbeaten team in the tournament, with four wins and a draw, they sit comfortably at the top of the table. Their all-round excellence, highlighted by efforts like Iyer's, has turned them into formidable opponents, leaving no room for easy runs or missed chances.



quite ready to throw him into the furnace of a live game just yet. Stephen Fleming and the medical staff are playing the long game, preferring a fully fit Dhoni for the business end of the season over a premature cameo in April. Even if he spends the evening in the dugout, his presence alone will be the loudest thing in the stadium.

SRH vs CSK: HEAD-TO-HEAD

CSK have not won in Hyderabad since 2018, losing on their last two trips to the city. However, they have a positive head-to-head record against SRH, winning 16 and losing only seven of their 23 encounters.

CAN CSK KEEP TRAVISHEK QUIET?

On the field, the narrative shifts from nostalgia to raw, modern aggression.

A promise kept: Frank Lampard helps Coventry secure promotion to PL after 25 years

Coventry City ended a 25-year absence from the Premier League by securing direct promotion with a dramatic late equaliser against Blackburn Rovers. The achievement marks a remarkable turnaround for the club after decades of financial struggles, lower-league football, and exile from their home stadium.

Mumbai. (Agency)

Once in a blue moon, a moment comes along that makes you believe fairytales are real, and one such story has unfolded in a small West Midlands city. Coventry City have ended their 25-year exile from the Premier



League, sealing direct promotion with a hard-fought 1-1 draw at Blackburn Rovers. Coventry, one of the founding members of the Premier League in 1992-93, had not played in the competition since their relegation in the 2000-01 season. So when centre-back Bobby Thomas scored the equaliser in the dying minutes, the 7,500 travelling fans were

bound to erupt like kids—crying, going topless, and holding up signs reading, "We're back." "It was an incredible moment (when Thomas scored)," Coventry City head coach Frank Lampard told Sky Sports. "We knew we were nearly there, but to finally get over the line after 25 years—wow! It's amazing. What the fans have gone through." As the

achievement sank in, Lampard, the former Chelsea and England midfielder, also became emotional, as this marked his first promotion as a manager. "This is a serious football club. These boys have achieved something unique. This is right up there for me," he said. "I was fortunate to be part of great Chelsea teams, winning league titles and Champions Leagues, but to do this—I'm very proud to be their manager." FINANCIAL BENEFITS?

This promotion to the top tier not only takes them back to the promised land but also brings in broadcast revenues worth around 120 million pounds. Beyond the base revenue, the club will benefit from merit payments, which are distributed based on a team's final league position. For every place higher a team finishes in the Premier League table, they typically earn an additional 2.5m to £3 million in prize money. Coventry had spent 34 consecutive seasons in England's top flight after their promotion in 1967, surviving countless.

Jacqueline Fernandez

Seeks To Turn Approver In Suresh Chandrashekhar Money Laundering Case

Jacqueline Fernandez has made a significant move in the ongoing money laundering case linked to alleged conman Suresh Chandrashekhar, expressing her willingness to turn an approver.

Jacqueline Fernandez Seeks to Turn Approver

In a key development, Jacqueline has moved an application before a Delhi court seeking to become an approver in the case. The court, taking note of her plea, has issued a notice to the Enforcement Directorate (ED) and sought its response. The matter is now scheduled for further hearing on April 20.

Delhi Court Asks Actor to Approach ED

During the proceedings, the court informed Jacqueline that she would have to follow due procedure and make a formal request to the ED if she intends to turn approver.

As per legal protocol, such a request must first be made to the federal probe agency. The ED would then record her statement and decide whether to move an application before the court recommending that she be granted approver status. At present, the decision rests with the agency, effectively placing the ball in the ED's court.



U-Turn in Ongoing Case

Jacqueline's move is being seen as a major shift in her stance in the high-profile case, which has been under investigation for alleged money laundering linked to Suresh Chandrashekhar. The development comes months after the Supreme Court refused to

quash the criminal proceedings against the actor, allowing the case to continue.

Case Background

The case revolves around Suresh Chandrashekhar, who is accused of orchestrating a ₹200 crore extortion racket, allegedly duping high-profile individuals including the family of former Ranbaxy promoters. The Enforcement Directorate named Jacqueline Fernandez as an accused in its money laundering probe, alleging that she received expensive gifts worth several crores from Chandrashekhar, which were suspected to be proceeds of crime.

Jacqueline has consistently denied any wrongdoing, maintaining that she was unaware of the illicit origin of these gifts.

Over the years, the case has seen multiple twists, including repeated questioning of the actor by the ED, legal challenges to quash proceedings, and public attention due to Chandrashekhar's claims and letters from jail. With Jacqueline now seeking to turn approver, her testimony could become a crucial element in the investigation, potentially shedding more light on the alleged financial network and the extent of involvement of those linked to the case.



Alia Bhatt's Sister Shaheen Bhatt Gets Engaged To Ishaan Mehra; Ananya Panday, Rohan Joshi And More Shower Love



In 2025, Alia Bhatt's sister, Shaheen Bhatt, made her relationship with fitness coach Ishaan Mehra Instagram official. Since then, the duo has been giving major couples on social media. Interestingly, the couple is now engaged. On April 17, Shaheen took to social media and shared a series of pictures with her partner to announce their union.

A while ago, Shaheen Bhatt shared pictures from her proposal, offering fans a glimpse into the intimate and heartfelt occasion. She was seen flaunting her stunning engagement ring while posing with Ishaan Mehra. The photos suggest that Ishaan chose a serene and picturesque setting to pop the question to his dream girl. Along with the pictures, Shaheen penned a quirky note that read, "We may have overdone this whole liking each other thing."

Soon after she shared the announcement, her post got flooded with congratulatory messages. Ananya Panday commented, "Shaheeeeen! Soooo happy for you. all the love and joy in the world." Navya Naveli Nanda wrote, "Congratulations Shaheeeen." Arjun Kapoor dropped a red heart emoji. Director Zoya Akhtar commented, "Congos and bongos." Shah Rukh Khan's manager Pooja Dadlani too put a comment that read, "Congratulations!!!!" Shaheen's ex boyfriend and comedian Rohan Joshi too congratulated the couple. He wrote, "OMG OMG CONGRATULATIONS." Even fans couldn't stop gushing over her engagement pictures. One fan wrote, "My heart is so full seeing this. What a beautiful surprise! Can't wait to hug you tight and say the biggest congratulations. Wishing you and Ishaan all the love and happiness in the world." Another fan wrote, "I dont even know you guys, I mean I know who you are @shaheenb but not personally. And yet, these photos make me really happy! Its probably the genuinely happy and positive vibes radiating from you both. All the very best for this new chapter!"

Tiger Shroff Grooves To Michael Jackson's Billie Jean, Pays Tribute: 'He Taught Me Everything'



Bollywood actor Tiger Shroff has paid a tribute to Michael Jackson as he performed on the iconic track Billie Jean and said that the King Of Pop taught him everything he knows about movement. The actor took to Instagram, where he shared a video of dancing on the number and performing the iconic steps like moonwalking and the leg shuffle. He added the song Billie Jean as the score to perform on.

"He taught me everything I know about movement. About presence. About what it means to give a stage everything you have," he wrote as the caption.

The Bollywood actor also tagged the "Michael" biopic page on Instagram. The upcoming follows the life of American singer Michael Jackson, covering the period from his involvement in the Jackson 5 in the 60s to his early solo career.

Jackson is portrayed by his nephew Jaafar Jackson in his film debut. The cast includes Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller, and Colman Domingo. The film is set to release on April 24.

Meanwhile, Tiger made his acting debut with the action romance Heropanti in 2014. He went on to star in the commercially successful action films Baaghi, Baaghi 2 and War. He tasted failure with big-budget action films such as Heropanti 2, Ganapath and Bade Miyan Chote Miyan and Baaghi 4. He has featured in Forbes India's Celebrity 100 list in 2018 and 2019.

His last film was Baaghi 4, directed by A. Harsha. The film stars Tiger Shroff, Sanjay Dutt, Harnaaz Sandhu and Sonam Bajwa. It is the fourth installment in the Baaghi film series.

It is an unofficial remake of the 2013 Tamil film Ainthu Ainthu Ainthu. In the film, a grieving man awakens from a coma and sets out to uncover the truth about his missing girlfriend who nobody believes even exists.



Tamannaah Bhatia Requests Paparazzi To Dim Lights While Comforting Crying Fan

Celebrity fan moments can be unpredictable... sometimes joyful, sometimes overwhelming, and occasionally deeply emotional. A recent interaction involving Tamannaah Bhatia is now going viral for all the right reasons, showing a softer, more compassionate side of stardom. The incident reportedly took place during one of Tamannaah's public appearances, where she was interacting with fans and posing for pictures. What began as a routine meet-and-greet quickly turned intense when a fan, upon seeing the actor up close, became visibly emotional. Overcome by the moment, the fan broke down in tears and found it difficult to compose herself.

Instead of moving on, Tamannaah paused and chose to stay back with the fan. She handled the situation with patience, speaking to her gently and encouraging her to calm down. The actor reportedly asked her to take a few deep breaths, ensuring she felt at ease during the interaction.

Realising that the environment might be adding to the fan's distress, Tamannaah also made a request to the paparazzi present at the venue to dim the lights. The move was aimed at reducing the intensity of the situation and helping the fan feel less overwhelmed. In addition, she offered the fan a bottle of water, a small but thoughtful gesture that helped her regain composure.

The video of the moment, shared by paparazzo Viral Bhayani on Instagram, has since drawn attention online, with many praising Tamannaah for her calm and considerate response.

Tamannaah Bhatia has built a strong career across Telugu, Tamil, and Hindi cinema. With nearly 89 films to her credit, she is regarded as one of the prominent actors in South Indian cinema. Over the years, she has received several honours, including three Santosham Film Awards, two SIIMA Awards, and the Kalaimamani Award.

